www.cgfrontline.com

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

■ वर्ष: 01 ■ अंक: 85 ■ जशपुर, 20 नवंबर 2026 (शुक्रवार) ■ पृष्ठ: 08 ■ मूल्य: 01 रूपये

एसएसपी साहब...लखनपुर थाना पुलिस के नजर में दबंगई दिखाकर वसूली अपराध नहीं

❐ छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

अंबिकापुर। लखनपुर थाना क्षेत्र के अमेरा ओपन खदान की ओर जाने वाली वाहनों से पिछले दो वर्षों से दबंगई दिखाकर अवैध वसूली का गोरखधंधा रूकने का नाम नहीं ले रहा है। अवैध वसूली का एक हिस्सा क्षेत्र के पुलिस महकमे तक पहुंचने की चर्चा खुलेआम हो रही है, जिस कारण कई शिकायतों के बाद भी कार्रवाई शून्य है। ट्रक चालकों का आरोप है कि मेन रोड से बस्ती होते हुए बैरियर तक पहुंचने में उनसे तीन-चार जगहों पर अलग-अलग नाम से रुपये की वसूली की जाती है। बताया जा रहा है कि दिनेश नामक युवक के छत्रछाया में यह धंधा चल रहा है। हैरत की बात यह है कि लखनपुर थाना पुलिस के नजर में यह अपराध नहीं है।

ट्रक चालकों ने सबूत के तौर पर पर्चियां दिखाते हुए बताया कि इनसे ग्राम पंचायत पीपरखार अमेरा के नाम पर 100 रुपये, ग्राम पंचायत अमेरा पीपरखार (ढाब) पार्किंग के नाम पर 100 रुपये, ग्राम चिलबिल में ट्रकों की पहरेदारी के नाम पर 200 रुपये, अमेरा खदान पार्किंग (निजी भूमि) के नाम पर 100 रुपये, कोयला परिवहन मालगाड़ी धूल गरदा एवं पानी छिड़काव का कर वसूली के नाम पर 200 रुपये, कुल मिलाकर एक वाहन से करीब 1000 रुपये तक वसूल किए जा रहे हैं। चालकों का कहना है कि एक ही वाहन से एक ही दिन में बार-बार पर्ची काटने से वे परेशान हैं। लखनपुर थाना प्रभारी से इस संबंध में बात करने पर उन्होंने पार्किंग सहित अन्य नामों पर हो रही अवैध वसूली को स्वीकार किया। ग्रामीणों को समझाइश देने की भी बात कही। साथ ही कहा कि, कुछ समय के बाद वसूली का सिलसिला पुनः शुरू हो जाता है। ऐसे में कहा जा सकता है कि पुलिस की नाकों के नीचे अवैध वसूली हो रही है। जिले के तेज तर्रार डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा राजेश अग्रवाल को इसे तत्काल संज्ञान में लेना चाहिए, ताकि वसूली के आड़ में चल रही दबंगई पर विराम लगे, नहीं तो कभी भी अप्रिय स्थिति निर्मित हो सकती है।





अमेरा खदान की ओर जाने पर रोजाना लुट रहे चालक, दे रहे प्रति ट्रक 1000 रुपये

ट्रक चालकों का दर्द वीडियो में हुआ कैद

वीडियो में चालकों ने अपने दर्द को साझा करते हुए कहा कि पहले से ही डीजल, मेंटेनेंस और किश्त के बोझ से मालिक दबे रहते हैं। ऊपर से रास्ते में जगह-जगह वसूली से कमाई खतरें में पड़ जाती है। अगर पर्ची नहीं कटवाते हैं तो आगे जाने नहीं दिया जाता है। विवाद, मारपीट, गाड़ी को क्षति पहुंचाने जैसी स्थिति कई बार बन चुकी है। गाड़ी रोक दी जाती है। फिजूल का एक हजार रुपये गंवाने के बाद वे कोयला लोड करवाने के लिए खदान तक पहुंच पाते हैं।

सरकारी आदेश और रेट लिस्ट करें सार्वजनिक

सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह वसूली किसके आदेश पर और किस नियम के तहत हो रही है। ग्राम पंचायत को पार्किंग, पानी छिड़काव या पहरेदारी के नाम पर मनमाने तरीके से पैसा वसूलने का अधिकार है या नहीं, यह जांच का विषय है। जिला परिषद के नाम पर भी वसूली का आरोप लग रहा है, आखिर जिला परिषद क्या है? चालकों ने प्रशासन से मांग की है कि इस अवैध वसूली की जांच कराई जाए। पर्ची काटने वालों की पहचान कर कार्रवाई हो और बैरियर तक जाने वाले मार्ग पर वसूली पर रोक लगाई जाए। अगर यह वसूली वैध है तो उसका सरकारी आदेश और रेट लिस्ट सार्वजनिक की जाए।

पार्किंग के नाम पर पैसा लिया जा रहा है। जिन लोगों को पैसा नहीं देना है, न दें। ग्रामीणों को कई बार समझाया गया, परंतु कुछ समय बाद यह पुनः चालू हो जाता है। यह कोई अपराध नहीं है।

प्रदीप जायसवाल,
थाना प्रभारी लखनपुर



साय सरकार का बड़ा फैसला :

चार आईएएस अफसरों को समय से पहले प्रमोशन

❐ छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के चार अधिकारियों को पदोन्नति दी है। मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह और गृह विभाग की प्रमुख सचिव निहारिका बारिक को अपर मुख्य सचिव (एसीएस) के पद पर प्रमोट किया गया है। वहीं, 2002 बैच के आईएएस अधिकारी डॉ. रोहित यादव और डॉ. कमलप्रीत सिंह को सचिव से प्रमुख सचिव बनाया गया है।

जानकारी के मुताबिक, चारों अधिकारियों की पदोन्नति जनवरी 2027 में प्रस्तावित थी, लेकिन सरकार ने निर्धारित समय से करीब डेढ़ महीने पहले ही उन्हें प्रमोशन दे दिया। इसे अधिकारियों के प्रशासनिक अनुभव और कार्यों के प्रति सरकार के भरोसे के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि, समय से पहले पदोन्नति का यह पहला मामला नहीं है। पूर्ववर्ती सरकारों के कार्यकाल में भी कुछ अधिकारियों को निर्धारित समय से पहले उच्च पदों पर पदोन्नति दी जा चुकी है।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सुबोध कुमार सिंह को दिल्ली से वापस बुलाकर अपना प्रमुख सचिव नियुक्त किया था। प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने और सरकारी कामकाज में सुधार की दिशा में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। वे मेहनती और परिणाम आधारित कार्यशैली वाले अधिकारी के रूप में पहचाने जाते हैं।

मच्छरदानी खरीदी में बड़ा खेल, 62 करोड़ के टेंडर पर उठे सवाल, CM और CS तक पहुंची शिकायत

❐ छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

मेडिकेटेड मच्छरदानी की खरीदी को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। मलेरिया प्रभावित क्षेत्रों में मुफ्त वितरण के लिए प्रस्तावित 62 करोड़ रुपये की 20 लाख मच्छरदानियों की खरीदी प्रक्रिया अब सवालों के घेरे में है। आरोप है कि स्वास्थ्य संचालनालय के रेट कॉन्ट्रैक्ट के लिए किए गए पत्राचार को नजरअंदाज कर छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन ने सीधे Gem पोर्टल के माध्यम से बल्क में टेंडर जारी कर दिया।

इस पूरी प्रक्रिया में नियमों और शर्तों को लेकर कई विसंगतियां सामने आने का दावा किया गया है। मामले की शिकायत मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव से कर खरीदी प्रक्रिया पर पुनर्विचार करने की मांग की गई है।

दरअसल, मलेरिया प्रभावित इलाकों में सरकार की ओर से लोगों को निशुल्क मेडिकेटेड मच्छरदानी वितरित की जाती है। सामान्य तौर पर इसके लिए मई-जून में टेंडर प्रक्रिया पूरी कर अक्टूबर से वितरण शुरू कर दिया जाता है। लेकिन इस बार टेंडर नवंबर के मध्य में जारी किए जाने पर भी सवाल उठ रहे हैं। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि देरी के साथ-साथ खरीदी का तरीका भी बदल दिया गया, जिससे प्रतिस्पर्धा सीमित होने की आशंका है।



रेट कॉन्ट्रैक्ट को दरकिनार कर Gem से बल्क खरीदी

शिकायत के मुताबिक, स्वास्थ्य संचालनालय ने मच्छरदानी की खरीदी के लिए CGMSC को रेट कॉन्ट्रैक्ट की व्यवस्था अपनाने के संबंध में पत्र लिखा था। रेट कॉन्ट्रैक्ट के जरिए अलग-अलग जिलों में जरूरत के मुताबिक सप्लाई की जा सकती है और निर्धारित दरों पर दोबारा भी ऑर्डर देने की सुविधा रहती है।

आरोप है कि इस व्यवस्था को अपनाने के बजाय CGMSC ने Gem पोर्टल के माध्यम से सीधे 20 लाख मच्छरदानियों की एकमुश्त खरीदी के लिए टेंडर जारी कर दिया। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि इससे स्थानीय और छोटे सप्लायरों के लिए प्रतिस्पर्धा करना मुश्किल हो सकता है।

300 रुपये में खरीदी पर सवाल, 250 रुपये बताई जा रही बाजार दर

मच्छरदानी की कीमत को लेकर भी गंभीर आपत्ति जताई गई है। शिकायत के अनुसार, प्रदेश में प्रति मच्छरदानी की खरीदी लगभग 300 रुपये की दर से प्रस्तावित है, जबकि बाजार में इसकी प्रचलित कीमत करीब 250 रुपये बताई जा रही है। इस अंतर के आधार पर प्रति नग 50 रुपये से अधिक की संभावित अतिरिक्त लागत का दावा किया गया है। यदि 20 लाख मच्छरदानियों की खरीदी में प्रति नग 50 रुपये का अंतर माना जाए तो कुल राशि करीब 10 करोड़ रुपये तक पहुंच सकती है।

62 करोड़ के बजट में 8 लाख अतिरिक्त मच्छरदानियां खरीदने का दावा

शिकायत में यह भी कहा गया है कि स्वास्थ्य संचालनालय ने प्रति मच्छरदानी लगभग 304 रुपये की अनुमानित दर के आधार पर बजट तैयार किया है, जबकि वर्तमान प्रचलित दर करीब 225 रुपये बताई गई है। शिकायतकर्ताओं का तर्क है कि यदि रेट कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से कम दर पर खरीदी की जाती तो इसी 62 करोड़ रुपये के बजट में लगभग 8 लाख अतिरिक्त मच्छरदानियां खरीदी जा सकती थीं।

राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम की गाइडलाइन का हवाला देते हुए कहा गया है कि 0.5 से अधिक API (औसत वार्षिक दर) वाले क्षेत्रों में दोबारा मच्छरदानी वितरण की जरूरत पड़ सकती है। ऐसे में नियमित और जरूरत के अनुसार सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए रेट कॉन्ट्रैक्ट की व्यवस्था महत्वपूर्ण बताई जा रही है।

टेंडर की शर्तों पर उठे सवाल

इस खरीदी प्रक्रिया में टेंडर की तकनीकी शर्तों को लेकर भी शिकायत की गई है। आरोप है कि प्रतिस्पर्धा को सीमित करने वाली शर्तें जोड़ी गई हैं। शिकायत में एटीसी के तहत 25 लाख रुपये की शर्त का उल्लेख करते हुए दावा किया गया है कि यह निर्धारित 80 प्रतिशत के दायरे से अधिक है।

शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि ऐसी शर्तों से कुछ चुनिंदा कंपनियों को फायदा मिल सकता है और अन्य संभावित सप्लायर प्रतिस्पर्धा से बाहर हो सकते हैं।

फसल बीमा के नाम पर किसानों के साथ धोखाधड़ी, नुकसान लाखों का, मुआवजा चंद रुपये - दीपक बैज

❐ छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

रायपुर। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को मिलने वाले मुआवजे को लेकर कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने दावा किया कि फसल नुकसान के बाद किसानों को पर्याप्त मुआवजा नहीं मिल रहा है, जबकि निजी बीमा कंपनियां मोटा मुनाफा कमा रही हैं। उन्होंने इसे फसल बीमा के नाम पर किसानों के साथ सुनियोजित लूट करार दिया और सरकार पर बीमा कंपनियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया।

बैज ने कहा कि प्रदेश के किसानों को फसल नुकसान के बदले बेहद कम मुआवजा मिल रहा है। कई किसानों को नुकसान के बावजूद मुआवजा नहीं मिल रहा, जिससे वे आर्थिक संकट और कर्ज के बोझ में फंस रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार किसान हितैषी होने का दावा करती है, लेकिन जमीनी स्तर पर किसानों को राहत नहीं मिल रही है।उन्होंने कहा कि किसानों के खातों से फसल बीमा का प्रीमियम नियमित रूप से काट लिया जाता है, लेकिन सूखा, ओलावृष्टि, बाढ़ या अन्य प्राकृतिक आपदाओं से फसल खराब होने पर मुआवजे के लिए उन्हें सर्वे और क्लेम सेटलमेंट के नाम पर दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। बैज ने कहा कि धान सहित अन्य फसलें उगाने वाले किसान मौसम की मार और कथित प्रशासनिक लापरवाही के बीच परेशान हैं। समय पर मुआवजा नहीं मिलने के कारण किसानों को साहूकारों से कर्ज लेने की नौबत आ रही है।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने पिछली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल का उल्लेख करते हुए कहा कि किसानों को आर्थिक मजबूती देने के लिए कर्जमाफी, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, समर्थन मूल्य और बोनस जैसी योजनाओं के माध्यम से सहायता दी गई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान भाजपा सरकार किसानों को राहत देने के बजाय



निजी बीमा कंपनियों के भरोसे छोड़ रही है। बैज ने फसल बीमा से जुड़ी पोर्टल और तकनीकी समस्याओं पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि यदि बीमा प्रक्रिया में तकनीकी गड़बड़ी है, तो किसानों के खातों से प्रीमियम कटने की प्रक्रिया प्रभावित क्यों नहीं होती? किसानों को मुआवजा देने के समय ही तकनीकी दिक्कतें सामने आने पर उन्होंने सरकार की जवाबदेही तय करने की मांग की। बैज ने आरोप लगाया कि सरकार और बीमा कंपनियों की मिलीभगत से किसानों के हितों की अनदेखी की जा रही है। हालांकि, ये सभी आरोप प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की ओर से लगाए गए हैं। इस संबंध में सरकार और संबंधित बीमा कंपनियों का पक्ष सामने नहीं आया है।

सड़क के लिए जमीन मांगने पहुंचीं महापौर, सिंहदेव ने कहा पहले मुआवजा दिलाइए

❐ छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

अंबिकापुर। शिवसागर बांध के किनारे पंचदेव मंदिर से गौरव पथ तक प्रस्तावित सड़क निर्माण को लेकर नगर निगम और पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव आमने-सामने आ गए हैं। सड़क निर्माण के लिए करीब दो एकड़ निजी जमीन की आवश्यकता है। इसकी बाजार कीमत लगभग 5 से 6 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इसी सिलसिले में महापौर मंजूषा भगत पार्षद दल के साथ टीएस सिंहदेव से मुलाकात कर जमीन उपलब्ध कराने की मांग करने पहुंचीं, लेकिन मुआवजे के मुद्दे पर सहमति नहीं बन सकी।

महापौर ने सिंहदेव को जमीन उपलब्ध कराने के संबंध में पत्र सौंपा। इस पर सिंहदेव ने स्पष्ट कहा कि सार्वजनिक उपयोग के लिए निजी जमीन का अधिग्रहण किया जाता है तो नियमानुसार उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए अथवा जमीन के बदले जमीन उपलब्ध कराई जानी चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया कि जब सड़क सार्वजनिक हित में बनाई जा रही है, तो जमीन का मुआवजा देने से सरकार पीछे क्यों हट रही है?

कलेक्टोरेट और नए बस स्टैंड को मिलेगा सीधा संपर्क

प्रस्तावित सड़क नमनाकला स्थित पंचदेव मंदिर से गौरव पथ तक शिवसागर बांध के किनारे बनाई जानी है। इसके निर्माण से कलेक्टोरेट, नगर निगम कार्यालय और नए बस स्टैंड के बीच सीधा संपर्क स्थापित हो सकेगा। फिलहाल इस मार्ग पर आवागमन के लिए कच्ची सड़क बनाई गई है। प्रस्तावित सड़क के लिए 20 से 30 फीट या उससे अधिक चौड़ाई की जमीन की आवश्यकता होगी, जिसमें राजपरिवार की निजी भूमि का हिस्सा शामिल है।



निगम के पास 6 करोड़ देने की क्षमता नहीं - महापौर

महापौर मंजूषा भगत ने मुलाकात के बाद कहा कि सिंहदेव ने पहले मौखिक सहमति दी थी, जिसके आधार पर सड़क निर्माण के लिए 3 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत कराई गई थी। अब मुआवजे की मांग सामने आने से निर्माण कार्य में मुश्किल खड़ी हो गई है। उन्होंने कहा कि नगर निगम की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वह 5 से 6 करोड़ रुपए का मुआवजा दे सके। निगम अपने प्लेसमेंट कर्मचारियों को भी समय पर वेतन देने में कठिनाई महसूस कर रहा है।

महापौर ने बताया कि इस मामले में मुख्यमंत्री और नगरीय निकाय मंत्री से चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि वे बड़ी उम्मीद लेकर सिंहदेव से मिलने पहुंची थीं, लेकिन जमीन उपलब्ध कराने को लेकर सहमति नहीं बन पाई और उन्हें निराश होकर लौटना पड़ा।

पहले की जमीन का भी नहीं मिला मुआवजा

टीएस सिंहदेव ने कहा कि वे पूर्व में भी सार्वजनिक निर्माण कार्यों के लिए अपनी जमीन उपलब्ध करा चुके हैं, लेकिन अब तक उसका मुआवजा नहीं मिला है। उन्होंने बताया कि यदि जमीन की कीमत 10 से 20 लाख रुपए होती तो वे स्वयं उपलब्ध करा देते, लेकिन यहां करीब 6 करोड़ रुपए की जमीन का मामला है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रस्तावित सड़क के पास उनकी सहमति के बिना निगम द्वारा चौड़ी नाली का निर्माण कराया गया है, जिसे लेकर उन्होंने न्यायालय में मामला दायर किया है।

विवाद के बाद हटाए गए कुलसचिव, प्रवीण अग्रवाल को मिला प्रभार

❐ छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

अंबिकापुर। संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय में कुलपति और कुलसचिव के बीच लंबे समय से चल रहे विवाद के बाद राजभवन ने बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की है। राजभवन के निर्देश पर कुलसचिव डॉ. शारदा प्रसाद त्रिपाठी को तत्काल प्रभाव से उनके पद से मुक्त कर दिया गया है। उनके स्थान पर उप कुलसचिव प्रवीण कुमार अग्रवाल को आगामी आदेश तक कुलसचिव का अस्थायी प्रभार सौंपा गया है। उन्हें कुलसचिव के साथ वित्तीय अधिकारों की जिम्मेदारी भी दी गई है।

जानकारी के अनुसार, राजभवन ने 18 नवंबर 2026 को कुलसचिव को हटाने संबंधी आदेश जारी किया था। राज्यपाल के अवर सचिव, लोक भवन रायपुर की ओर से जारी पत्र के पालन में कुलपति ने डॉ. त्रिपाठी को तत्काल प्रभाव से कुलसचिव के दायित्वों से भारमुक्त कर दिया।

योग्यता और वित्तीय अनियमितताओं को लेकर उठे थे सवाल

विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. राजेंद्र लोकपाले और कुलसचिव डॉ. शारदा प्रसाद त्रिपाठी के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। कुलपति ने कुलसचिव की शैक्षणिक योग्यता और इस पद पर उनकी नियुक्ति की पात्रता को लेकर सवाल उठाए थे। इसके अलावा विश्वविद्यालय में विकास कार्यों पर खर्च की गई राशि में कथित अनियमितताओं की शिकायत भी राज्यपाल से की गई थी।



मार्च 2024 में हुई थी नियुक्ति

उल्लेखनीय है कि डॉ. शारदा प्रसाद त्रिपाठी जनकपुर स्थित शासकीय महाविद्यालय में सहायक प्राध्यापक के पद पर कार्यरत थे। राज्य शासन ने उन्हें प्रतिनियुक्ति पर संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय का कुलसचिव नियुक्त किया था। मार्च 2024 में उन्होंने कुलसचिव का पदभार संभाला था। अब उनकी जगह प्रवीण कुमार अग्रवाल को विश्वविद्यालय के प्रशासनिक और वित्तीय कार्यों की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

कुलपति ने इस संबंध में राज्यपाल को पत्र भेजकर कार्रवाई की मांग की थी।

बताया जा रहा है कि शिकायत के बाद राजभवन ने कुलसचिव को हटाने के लिए उच्च शिक्षा विभाग को पत्र लिखा था। इसके बाद 18 नवंबर को आदेश जारी हुआ और कुलपति ने डॉ. त्रिपाठी को पदमुक्त कर दिया।

दो अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में तीन लोगों को आई गंभीर चोटें

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

बिश्रामपुर। दो अलग-अलग सड़क हादसों में तीन लोगों को गंभीर चोट आई हैं। लटोरी पुलिस ने बताया कि 17 नवंबर की शाम करीब 5.30 बजे ग्राम पंचायत कल्याणपुर करेरपारा में भजन राम मानिकपुरी के नाती 18 वर्षीय प्रकाश दास घर के बाहर बैठा था। तभी कल्याणपुर बाजार की तरफ से आ रही पिकअप वाहन क्रमांक यूपी 64 बीटी 3357 के चालक ने तेज व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए प्रकाश को टक्कर मार दिया, जिससे युवक दूर तक उछल गया। दुर्घटना में युवक के कमर, सीना, जबड़ा और पूरे शरीर में चोटें आई हैं। जिसे उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जयनगर पुलिस ने बताया कि सुमित कुमार सिंह और उसका दोस्त राहुल सिंह गत दिनों 16 नवंबर की रात करीब साढ़े आठ बजे स्प्लेंडर मोटरसाइकिल से अंबिकापुर जा रहे थे। तभी राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 43 पर केनापारा तेलईकछार पुलिया के पास छोटी हाथी वाहन क्रमांक यूपी 64 एटी 6063 के चालक ने तेज रफ्तार वाहन चलाते हुए बाइक को सामने से टक्कर मार दी। दुर्घटना में दोनों बाइक सवार के पैर और शरीर में चोटें आई। जिन्हें उपचार हेतु सूरजपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

नौकरी व मुआवजा को लेकर रेहर खदान में ग्रामीणों ने घंटों किया तालाबंदी



प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

बिश्रामपुर। नौकरी एवं मुआवजे की मांग को लेकर प्रभावित ग्रामीणों ने गुरुवार को गायत्री एवं रेहर खदान में तालाबंदी कर आंदोलन किया। सुबह पांच बजे से शुरू हुआ आंदोलन दोपहर करीब ढाई बजे तक चला। एसईसीएल अधिकारियों द्वारा मांगों के निराकरण के संबंध में लिखित आश्वासन दिए जाने के बाद हड़ताल समाप्त हुई। एसईसीएल बिश्रामपुर क्षेत्र की रेहर-गायत्री भूमिगत परियोजना से प्रभावित भू-स्वामियों की नौकरी और मुआवजे से संबंधित मांगों को लेकर चल रहे विवाद के बीच एसईसीएल प्रबंधन ने अपनी ओर से वस्तुस्थिति स्पष्ट की है। क्षेत्रीय महाप्रबंधक कार्यालय बिश्रामपुर द्वारा ग्राम पंचायत गेतरा, मानी, पोड़ी एवं जोबगा के सरपंचों को भेजे गए लिखित पत्र में बताया गया है कि प्रभावित परिवारों को मुआवजा वितरण लगातार हो रहा है एवं रोजगार उपलब्ध कराने की प्रक्रिया नियमानुसार जारी है। प्रबंधन ने विभिन्न स्तरों पर हुई प्रगति का भी विस्तृत ब्यौरा दिया है। प्रबंधन के अनुसार गायत्री भूमिगत परियोजना में अधिग्रहित भूमि के एवज में मुआवजा वितरण की प्रक्रिया वर्तमान में प्रगति पर है। अब तक लगभग 21 करोड़ रुपए का मुआवजा प्रभावित भू-स्वामियों को भुगतान किया जा चुका है। वहीं रोजगार प्रदान करने की प्रक्रिया भी प्रक्रियाधीन है। इसके लिए प्रबंधन द्वारा वरीयता सूची तैयार कर ली है विधिक एवं प्रशासनिक अनुमोदन के अंतिम चरण में है। पत्र में यह भी बताया गया है कि गायत्री परियोजना के अंतर्गत गेतरा में 17, जोबगा में 95 एवं पोड़ी में 158, इस प्रकार कुल 270 रोजगार सृजित किए गए हैं। एसईसीएल बिलासपुर से शीघ्र अनुमोदन प्राप्त होने के बाद नियमानुसार रोजगार प्रदान करने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। रेहर भूमिगत फेज 1 परियोजना के संबंध में प्रबंधन ने बताया कि अधिग्रहित भूमि के दावों के निराकरण के लिए गेतरा, मानी एवं पोड़ी ग्रामों के आवश्यक स्टेटमेंट 5 एवं 6 तैयार किए जाने की प्रक्रिया पूरी की गई है। तीनों गांवों की अधिग्रहित भूमि की मुआवजा सूची (वन-ए एवं वन-बी) तैयार कर अनुमोदन के लिए एसईसीएल बिलासपुर भेजने की प्रक्रिया लगभग पूर्ण कर ली गई है। पत्र में स्पष्ट किया गया है कि मानी, गेतरा एवं पोड़ी के स्टेटमेंट 5 के प्रशासनिक अनुमोदन के लिए प्रकरण सूरजपुर तहसील कार्यालय में लंबित हैं। अनुमोदन प्राप्त होते ही तीनों गांवों की अधिग्रहित भूमि की मुआवजा सूची एसईसीएल बिलासपुर को स्वीकृति के लिए भेज दी जाएगी।इस दौरान सूरजपुर जनपद अध्यक्ष स्वाति संत सिंह, पोड़ी सरपंच खेलनदन सिंह, गेतरा सरपंच प्रतिनिधि रामस्वरूप, मानी सरपंच प्रतिनिधि रामप्रसाद, सभी पंचायत के उप सरपंच, पंच सहित बड़ी संख्या ग्रामीण उपस्थित रहे।

कोटपा एक्ट के तहत बिश्रामपुर में 50 चालानी कार्रवाई

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

बिश्रामपुर। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत तंबाकू एवं अन्य तंबाकू उत्पादों के सेवन पर नियंत्रण तथा धूम्रपान से होने वाले दुष्प्रभावों की रोकथाम के लिए जिले में जागरूकता एवं चालानी कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में कलेक्टर रेना जमील के निर्देश एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के मार्गदर्शन में खाद्य एवं औषधि प्रशासन तथा पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने बिश्रामपुर के कई ठेलों में कार्रवाई की है। कार्रवाई के दौरान कोटपा एक्ट 2003 के तहत 50 चालानी कार्रवाई करते हुए 5 हजार रूपए का जुर्माना वसूला गया। टीम ने सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान एवं तंबाकू उत्पादों के सेवन पर प्रतिबंध के संबंध में लोगों को जागरूक किया तथा नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की। कोटपा एक्ट की धारा 4 के तहत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान प्रतिबंधित है।

वहीं धारा 6 (ब) के तहत 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को तंबाकू उत्पादों की बिक्री प्रतिबंधित है। कार्रवाई के दौरान संबंधित दुकानों एवं सार्वजनिक स्थानों पर नो स्मोकिंग तथा नाबालिगों को तंबाकू उत्पादों की बिक्री प्रतिबंधित होने संबंधी सूचना बोर्ड लगाने के निर्देश भी दिए गए।

कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल में बाल दिवस पर दिया गया न्योता भोज



प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

बिश्रामपुर। शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बिश्रामपुर में प्राचार्य आशीष कुमार भट्टाचार्य के मार्गदर्शन में आज हर्षोल्लास के साथ बाल दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया। उल्लेखनीय है कि 14 से 16 नवंबर तक भगवान बिरसा मुंडा जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों की व्यस्तता के कारण विद्यालय में गुरुवार को इस विशेष उत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण विद्यालय के शिक्षक-शिक्षिकाओं द्वारा आयोजित न्योता भोज रहा, जिसमें विद्यालय की 700 छात्राओं को पौष्टिक भोजन परोसा गया। आयोजन का प्रमुख उद्देश्य बच्चों के प्रति स्नेह और सम्मान प्रकट कर उन्हें स्कूल के वातावरण से आत्मीय रूप से जोड़ना है। न्योता भोज के माध्यम से विद्यार्थियों में सामाजिक समरसता, आपसी भाईचारे और सामुदायिक सहभागिता की भावना को बढ़ावा दिया गया, ताकि छात्राओं को घर जैसा अपनापन मिल सके और उनके सर्वांगीण विकास व पोषण स्तर में सुधार हो। कार्यक्रम में सहायक संचालक अजय कुमार, सुरजपुर बीईओ हरेंद्र सिंह, बीआरसी मनोज कुमार मंडल, नगर पंचायत अध्यक्ष विश्रामपुर निर्मला यादव, पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष राजेश यादव, एसएमडीसी सदस्य तोलाराम जैन एवं शशि नान्हू मुख्य रूप से शामिल हुए।

जयनगर सहकारी समिति में हुई धान खरीदी की शुरुआत

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

बिश्रामपुर। आदिम जाति सहकारी समिति जयनगर में शासन के मंशानुरूप धान खरीदी का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा मंडल अध्यक्ष हरीश राजवाड़े उपस्थित रहे। अन्य अतिथियों में पिलखा नायब तहसीलदार श्रीमती मीना सिंह, भाजपा जिला उपाध्यक्ष देवधन राम बिंझिया, सुरेन्द्र राजवाड़े, देवशरण सिंह, जयनगर सरपंच श्रीमती राधा बाई, जनपद सदस्य श्रीमती धनेश्वरी सिंह, मंजित सिंह भामरा उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरूआत सर्वप्रथम मां भारती एवं छत्तीसगढ़ महतारी की छाया चित्र पर दीप प्रज्वलित कर व धान बेचने वाले प्रथम किसान बुधराम राजवाड़े परसापारा व सहोदर राजवाड़े तेलईकछार की धान खरीद कर किया गया। स्वागत भाषण व प्रतिवेदन धान खरीदी केंद्र के आपरेटर कमल बिंझिया ने प्रस्तुत किया। इसके पश्चात सुरेन्द्र राजवाड़े ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव की सरकार अब किसानों की धान को प्रति एकड़ 21 क्विंटल में 3100 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदी करेगी। जिन किसानों की धान 21 क्विंटल नहीं पहुंच पा रही है,



उसकी अंतर की राशि को सरकार पूरी करेगा। देवधन राम बिंझिया ने कहा कि भाजपा सरकार में किसान की खुशहाली है। एक समय था, जब किसान चावल खरीद कर खाते थे और आज बेच रहे हैं। इस अवसर पर मुख्य रूप से राजेन्द्र प्रसाद गर्वटिया, संतोष सिंह, बुधराम राजवाड़े, सहोदर राजवाड़े, पार्वतीपुर सरपंच चंद्रदेव तिर्की, विधि गर्ग, बूलचू राजवाड़े, लवन राजवाड़े, देवनारायण राजवाड़े, देवनारायण मिस्त्री, कृष्ण पाल बिंझिया, निर्कुंज बिंझिया, अरविंद सिंह, हेमसाय राजवाड़े, प्रकाश बिंझिया, लाल साय, प्रशान्त बिंझिया, रिषभ राजवाड़े, संजय बिंझिया, विरेन्द्र बिंझिया, मनियारो राजवाड़े, रीता भगत व अन्य उपस्थित रहे। मंच संचालन कृषक देशरण सिंह एवं आभार लाल साय ने व्यक्त किया।

15 सूत्रीय मांगों को लेकर क्रमिक भूख तीसरे दिन भी जारी



प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

बिश्रामपुर। संयुक्त कोयला मजदूर संघ एटक बिश्रामपुर क्षेत्र द्वारा ठेका श्रमिकों की 15 सूत्रीय लंबित मांगों के निराकरण की मांग को लेकर 17 नवंबर से महाप्रबंधक कार्यालय के समक्ष जारी सात दिवसीय क्रमिक भूख हड़ताल आज तीसरे दिन भी जारी रही। संघ के क्षेत्रीय सचिव पंकज कुमार गर्ग ने बताया कि आज तीसरे दिन ठेका श्रमिक क्रमशः गणेश कुमार, मनोज सिंह, बृजलाल, रामनाथ, फिलिप एक्का, विवेक कुमार, विश्वनाथ सिंह, रामकुमार, फूल साय, मिलन सिंह बैठे रहे। ठेका श्रमिकों की मांग है कि सभी खदानों में कार्य समिति का अनिवार्य गठन किया जाए। सभी ठेका श्रमिकों को नियमानुसार नियुक्ति पत्र और पहचान पत्र प्रदान किया जाए।कोयला ट्रांसपोर्ट, साइडिंग, सोलर प्लांट एवं खान परिसर के सभी कामगारों को एचपीसी वेज का भुगतान हो। बायोमेट्रिक व उपस्थिति रजिस्टर में हाजिरी दर्ज हो एवं प्रति माह 26 दिन का कार्य सुनिश्चित किया जाए। हर महीने की 7 तारीख तक वेतन भुगतान और अनिवार्य वेतन पर्ची दी जाए। कॉरपोरेट बैंक खातों से वेतन भुगतान हो ताकि श्रमिकों को कॉरपोरेट बीमा का लाभ मिल सके। बोनस/पीएलआई का पूर्ण भुगतान हो तथा गायत्री एवं केतकी खदान के वर्ष 2024-25 का बकाया बोनस तुरंत दिया जाए। खदानों में सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन हो और दुर्घटनाओं को छुपाने की प्रथा पर तत्काल रोक लगे। गायत्री एवं केतकी खदान के आसपास रोजगार के नाम पर हो रही अवैध धन उगाही की उच्चस्तरीय जांच कराकर भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाए। पूर्व में वेतन से काटी गई सीएमपीएफ राशि की तत्काल वापसी या समायोजन किया जाए।

धान खरीदी में लगे अधिकारियों-कर्मचारियों के अवकाश पर रोक

बलरामपुर, छ.ग. फ्रंटलाइन। कलेक्टर श्रीमती चंदन संजय त्रिपाठी ने खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में धान खरीदी कार्य में लगे अधिकारियों और कर्मचारियों के सभी प्रकार के अवकाश और मुख्यालय छोड़ने पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। धान खरीदी के लिए नोडल समिति, जिला स्तरीय नोडल, फ्लाइंग स्क्वॉड और चेक पोस्ट सहित विभिन्न स्तरों पर अधिकारियों-कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। आईसीसी अलर्ट, भौतिक सत्यापन, अवैध धान भंडारण और परिवहन पर निगरानी तथा शनिवार को होने वाले अनिवार्य भौतिक सत्यापन जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।

अपरिहार्य परिस्थिति में अवकाश की आवश्यकता होने पर संबंधित अधिकारी-कर्मचारी को कारण बताते हुए कलेक्टर के समक्ष आवेदन देना होगा। स्वीकृति मिलने के बाद ही वे अवकाश पर जा सकेंगे।

उत्तर प्रदेश से लाया जा रहा अवैध धान जब्त

दो ट्रैक्टरों सहित 116 बोरी धान डिंडो चौकी के सुपुर्द

बलरामपुर, छ.ग. फ्रंटलाइन। सीमावर्ती राज्यों से धान के अवैध परिवहन पर रोक के लिए प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। इसी क्रम में उड़नदस्ता प्रभारी नायब तहसीलदार श्री आई.सी. यादव एवं मंडी सचिव श्री वीरेंद्र ठाकुर की संयुक्त टीम ने बिना वैध दस्तावेज़ के धान ले जा रहे दो ट्रैक्टर पकड़े।

पहली कार्रवाई में टीम ने तेजस्वर यादव के महिंद्रा ट्रैक्टर को रोका। इस ट्रैक्टर से उत्तर प्रदेश से 53 बोरी धान बिना दस्तावेज़ के कामेश्वरनगर ले जाया जा रहा था। दूसरी कार्रवाई में ग्राम रौंदा के नदी किनारे चूनापत्थर निवासी कृष्ण कुमार गुप्ता का धान से लदा ट्रैक्टर जब्त किया गया। दोनों ट्रैक्टरों सहित कुल 116 बोरी धान जब्त कर डिंडो



चौकी के सुपुर्द किया गया है। प्रकरण में छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 के तहत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि धान उपार्जन व्यवस्था को प्रभावित करने वाले अवैध परिवहन और बिक्री पर सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

मां भगवती जागरण भजन संध्या में गूंजे भक्ति के सुर



प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

बिश्रामपुर। धार्मिक और सामाजिक कार्यों में अग्रणी श्री नवयुवक दुर्गा मंडल बिश्रामपुर द्वारा आयोजित 23 वाँ वार्षिक उत्सव एवं मां भगवती जागरण भजन संध्या श्रद्धा, भक्ति और उल्लास के वातावरण में संपन्न हुआ। जिसमें मंडल के सभी सदस्यों ने स्वागत की कड़ी में हनुमान मंदिर के पुजारी भोला महाराज एवं मंदिर के संरक्षक सुशील जैन, जमड़ी मंदिर के संरक्षक अशोक महाराज, श्री नवयुवक दुर्गा मंडल के संरक्षक धर्मवीर अग्रवाल, मदन अग्रवाल सहित सभी सभी पदाधिकारी एवं सदस्यों का स्वागत चुनरी और तिलक से किया गया। नगर के बस स्टैंड में स्थित श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम में क्षेत्रभर से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लेकर मां भगवती के भजनों का रसास्वादन किया।

जागरण की शुरुआत मां की आरती एवं अखंड ज्योत प्रज्वलन के साथ हुई, जिसके बाद रात भर भक्ति सुरों की गूंज मंदिर परिसर में बनी रही।जबलपुर से पधारे भजन गायक हिना सिंह, शुभम गुप्ता, अंतरा शुक्ला, वीरेंद्र सिंह, कैलाश चौधरी एवं हरदीप सिंह और सक्षम महोबिया ने अपनी मधुर वाणी में मां भगवती के भजनों की ऐसी प्रस्तुति दी कि उपस्थित श्रद्धालु भक्ति भाव में झूम उठे। कार्यक्रम की विशेष आकर्षण रही जबलपुर की जीवंत झांकी महिला कलाकरों द्वारा जिसमें देवी-देवताओं के अद्भुत रूपों का मनमोहक प्रदर्शन किया गया। मध्य रात्रि में माता रानी को चुनरी भेंट, डांडिया नृत्य, सवामणि प्रसाद वितरण तथा अखंड ज्योत दर्शन जैसे आयोजन श्रद्धालुओं के लिए भावनात्मक एवं धार्मिक अनुभव का केंद्र बने।कार्यक्रम के अंत में मंडल के पदाधिकारियों ने उपस्थित श्रद्धालुओं के प्रति आभार व्यक्त करते हुए आगामी 25 वाँ वार्षिक उत्सव मनाने का संकल्प लिया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में मंडल के राकेश अग्रवाल, अजय मित्तल, अरविंद मित्तल, रतन अग्रवाल, शंकर अग्रवाल, मनोज मित्तल, सुनील मित्तल, अजय अग्रवाल, राजेश सोनी, चाहत अग्रवाल, नेहल अग्रवाल, क्षितिज चंदेल, सजल मित्रा, अभिनव मित्तल, नैतिक अग्रवाल एवं अन्य सक्रिय रहे।

कस्टम मिलिंग का चावल जमा न करने पर राजपुर की सर्वमंगला राइस मिल सील



बलरामपुर, छ.ग. फ्रंटलाइन। कलेक्टर श्रीमती चंदन संजय त्रिपाठी के निर्देश पर जिले की राइस मिलों का भौतिक सत्यापन किया जा रहा है। सत्यापन में सामने आया कि राजपुर स्थित सर्वमंगला राइस मिल ने कस्टम मिलिंग का चावल जमा नहीं किया था। सूचना के बाद भी मिल बंद रखी गई थी। इस पर खाद्य अधिकारी, खाद्य निरीक्षक और मंडी निरीक्षक की संयुक्त टीम ने मिल को सील कर दिया।

जिला प्रशासन ने सभी राइस मिलों को शेष चावल 10 दिन के भीतर नागरिक आपूर्ति निगम में जमा करने के निर्देश दिए हैं। जिन मिलों में धान का स्टॉक कम पाया जाएगा या जो तय समय में चावल जमा नहीं करेंगी, उन पर छत्तीसगढ़ कस्टम मिलिंग चावल उपार्जन आदेश 2016 के तहत कड़ी कार्रवाई होगी। ऐसी मिलों को ब्लैक लिस्ट किया जाएगा और उनकी बैंक गारंटी राजसात की जाएगी।

सरहरी पंचायत में हुए निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार का आरोप

शिकायतों के बाद भी कार्रवाई नहीं होने से ग्रामीणों में नाराजगी

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

सूरजपुर। ग्राम पंचायतों में विकास के नाम पर आने वाली सरकारी राशि का उद्देश्य ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना है, लेकिन जब विकास कार्य केवल दस्तावेजों और फाइलों तक सीमित रह जाए तथा धरातल पर निर्माण की नींव तक दिखाई न दे, तो पंचायत व्यवस्था की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े होना स्वाभाविक है। ऐसा ही एक गंभीर मामला प्रतापपुर क्षेत्र के ग्राम पंचायत सरहरी से सामने आया है। यहां ग्रामीणों और शिकायतकर्ता पुष्पेंद्र गुप्ता सहित अन्य ग्रामीणों ने पंचायत में अलग-अलग वर्षों के दौरान स्वीकृत निर्माण कार्यों की राशि में कथित गड़बड़ी और सरकारी धन के दुरुपयोग के गंभीर आरोप लगाए हैं। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि पंचायत में साइकिल स्टैंड, पानी टैंकर, पानी टंकी, नाली निर्माण, सामुदायिक शौचालय मरम्मत, तालाब गहरीकरण और अतिरिक्त कक्ष निर्माण सहित कई कार्यों हेतु राशि निकाली गई, लेकिन कई कार्य आज तक पूरे नहीं हुए। कुछ मामलों में ग्रामीणों का दावा है कि मौके पर निर्माण कार्य शुरू तक नहीं हुआ, जबकि सरकारी राशि खर्च होने अथवा निकाल लिए जाने की बात सामने आ रही है। यदि शिकायत में लगाए गए आरोप जांच में सही पाए जाते हैं, तो यह केवल पंचायत स्तर की अनियमितता नहीं, बल्कि सरकारी योजनाओं की निगरानी व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल होगा। शिकायतकर्ता के अनुसार वर्ष 2021-22 में हाई सेकेंडरी स्कूल परिसर में साइकिल स्टैंड निर्माण के लिए लगभग



5 लाख रुपये की स्वीकृति राशि निर्धारित थी। आरोप है कि इसमें करीब 2 लाख रुपये का कथित गबन हुआ, जबकि स्कूल परिसर में आज तक साइकिल स्टैंड का निर्माण नहीं कराया गया। स्वीकृत राशि का भुगतान किस आधार पर किया गया और निर्माण की गुणवत्ता तथा भौतिक सत्यापन किसने किया। इसी तरह वर्ष 2023-24 में पंचायत में पानी की समस्या दूर करने के लिए टैंकर लगाने के नाम पर लगभग एक लाख रुपये की राशि में गड़बड़ी का आरोप लगाया गया है। शिकायत में पूर्व सरपंच धनपत सिंह और तत्कालीन पंचायत सचिव विकास पटेल की भूमिका पर सवाल उठाए गए हैं। आरोप है कि राशि के उपयोग को लेकर स्पष्ट जानकारी नहीं दी जा रही है। शिकायत में पंचायत सचिव विकास पटेल के कार्यकाल से जुड़े विभिन्न मदों में कथित वित्तीय अनियमितताओं का उल्लेख किया गया है। इनमें पानी टंकी निर्माण की राशि, हाई स्कूल सरहरी में साइकिल स्टैंड निर्माण, नाली निर्माण के लिए स्वीकृत राशि, सामुदायिक शौचालय की मरम्मत, तालाब गहरीकरण तथा वनवासी सेवा मंडल में अतिरिक्त कक्ष निर्माण शामिल हैं। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि कई कार्यों के लिए सरकारी धन निकाले जाने के बावजूद निर्माण अधूरे हैं या मौके पर काम दिखाई नहीं देता। वनवासी सेवा मंडल के अतिरिक्त कक्ष निर्माण को भी अधूरा बताते हुए उसकी राशि के उपयोग की जांच की मांग की गई है। ग्रामीणों के अनुसार वर्ष 2022, 2023, 2024 और 2025 के विभिन्न कार्यों की वित्तीय लेनदेन और निर्माण की स्थिति की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। ग्रामीणों का दावा है कि इन आरोपों के संबंध में उनके पास दस्तावेज और अन्य प्रमाण उपलब्ध हैं। ग्रामीणों के अनुसार इस मामले की जानकारी पहले भी जनपद पंचायत और जिला प्रशासन को दी जा चुकी है। शिकायत मुख्यमंत्री के टोल फ्री नंबर पर भी दर्ज कराई गई है, लेकिन आज तक कोई ठोस कार्रवाई दिखाई नहीं दी। ग्रामीणों ने जनपद सीईओ श्री की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि उनके पदभार संभालने के बाद से पंचायतों में निगरानी और जवाबदेही की स्थिति कमजोर हुई है तथा कई जगह मनमानी की शिकायतें सामने आ रही हैं। सरहरी को जागरूक ग्राम पंचायतों में गिना जाता है। यहां पढ़े-लिखे और अपने अधिकारों के प्रति सजग ग्रामीण निवास करते हैं।

इसके बावजूद यदि विकास कार्यों में गड़बड़ी के आरोप लगातार सामने आ रहे हैं और कार्रवाई नहीं हो रही, तो यह प्रशासनिक निगरानी व्यवस्था के लिए चिंता का विषय है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से निष्पक्ष जांच के लिए उच्चस्तरीय टीम गठित करने, सभी संबंधित वर्षों के वित्तीय अभिलेखों की जांच कराने और दोषी पाए जाने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की मांग की है।

धूमधाम से मना भगवान बिरसा मुंडा का जन्मोत्सव सैकड़ों नागरिकों ने दी श्रद्धांजलि

हनुमंत हिन्दू सेवा संघ का आयोजन

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन



सूरजपुर। भगवान बिरसा मुंडा के जन्मोत्सव पर श्री हनुमंत हिन्दू सेवा संघ द्वारा जर्जानगर जरही स्थित सांस्कृतिक भवन में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में क्षेत्र के प्रबुद्ध नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और भगवान बिरसा मुंडा के जीवन, संघर्ष, त्याग एवं बलिदान को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में लवकेश पैकरा उपस्थित रहे। वहीं विशिष्ट अतिथियों में पूरन राम राजवाड़े, लाल साय सिंह पावले, देवपाल पैकरा, अशोक गुप्ता, अंगद रजवाड़े एवं दसराज सिंह सहित अन्य गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति रही। आयोजन का उद्देश्य भगवान बिरसा मुंडा जी के विचारों, सामाजिक चेतना, जनजातीय अस्मिता और देश के प्रति उनके योगदान को जन-जन तक पहुंचाना रहा। भगवान बिरसा मुंडा ने अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध संघर्ष करते हुए आदिवासी समाज के अधिकारों, स्वाभिमान और जल-जंगल-जमीन की रक्षा के लिए ऐतिहासिक आंदोलन का नेतृत्व किया था। उनका जीवन आज भी समाज को अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने, एकजुट रहने और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने की प्रेरणा देता है। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों एवं नागरिकों ने भगवान बिरसा मुंडा के आदर्शों को अपने जीवन में आत्मसात करने तथा समाज में एकता, शिक्षा, जागरूकता और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने का संकल्प लिया। वक्ताओं ने उनके संघर्षपूर्ण जीवन को याद करते हुए कहा कि भगवान बिरसा मुंडा केवल एक जनजातीय नायक ही नहीं, बल्कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में साहस, स्वाभिमान और बलिदान के प्रतीक हैं। उनका योगदान आने वाली पीढ़ियों के लिए सदैव प्रेरणास्रोत बना रहेगा। कार्यक्रम का संचालन श्री हनुमंत हिन्दू सेवा संघ के संयोजक दिनेश पांडेय ने किया। कार्यक्रम का समापन भगवान बिरसा मुंडा जी के आदर्शों को याद करते हुए सामाजिक एकता और राष्ट्रहित में मिलकर कार्य करने के संदेश के साथ हुआ।

अदाणी फाउंडेशन की पहल से 108 जरूरतमंद बच्चों को मिले स्कूल बैग, खुशी से खिले नौनिहालों के चेहरे

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

रामानुजनगर। शिक्षा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से अदाणी फाउंडेशन ने रामानुजनगर विकासखण्ड के प्राथमिक शाला पतरापाली, अहीरपारा, छापरपारा और शासकीय प्राथमिक शाला खालपारा के 108 जरूरतमंद छात्र-छात्राओं को निःशुल्क स्कूल बैग वितरित किए। बैग पाकर नन्हे-मुन्ने बच्चों के चेहरे खुशी से खिल उठे। अब तक किताबें हाथों में या पॉलीथीन में लेकर आने वाले बच्चों को बैग मिलने पर विशेष उत्साह दिखा। एक बच्चे ने कहा, 'मुझे बैग मिल गया, अब मैं रोज स्कूल आऊँगा और खूब पढ़कर डॉक्टर बनूँगा।' बच्चों ने फाउंडेशन को 'थैंक्यू' कहकर आभार व्यक्त किया।



इस अवसर पर अनिल जायसवाल ने कहा कि कई जरूरतमंद बच्चों के पास किताबें तो होती हैं, लेकिन बैग नहीं होता। इसी आवश्यकता को ध्यान में रखकर यह पहल की गई है। फाउंडेशन आगे भी ऐसे विद्यालयों को चिह्नित कर बच्चों की मदद करेगा, ताकि पढ़ाई के प्रति रुचि बढ़े। ग्रामीणों ने पहल की सराहना करते हुए कहा कि इससे बच्चों को नियमित स्कूल आने और मन लगाकर पढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। कार्यक्रम में संकुल समन्वयक योगेश साहू, प्रधान पाठक के.के. यादव, कर्मेन्द्र सिंह, पी पी कुजूर, सोहन सिंह, उर्मिला सिंह, अनीता सिंह, रघुनाथ जायसवाल, अजय साहू, प्रवीणा, आरती पटेल, अंजली कंवर सहित शिक्षक और छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।

जिला पंचायत की सामान्य सभा में विकास एवं जनहित के मुद्दों पर विस्तृत चर्चा

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन



अम्बिकापुर। जिला पंचायत की सामान्य सभा की बैठक गुरुवार को जिला पंचायत उपाध्यक्ष देव नारायण यादव की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी रोमा श्रीवास्तव सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में जिले में संचालित विभिन्न शासकीय योजनाओं एवं विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विभाग, महिला एवं बाल विकास, उद्यानिकी, कृषि तथा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना सहित विभिन्न विभागों से जुड़े विषयों पर विस्तारपूर्वक चर्चा हुई। धान खरीदी व्यवस्था को सुचारू एवं पारदर्शी बनाए रखने, किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। पशुपालन विभाग की गतिविधियों तथा किसानों और पशुपालकों को दी जा रही सुविधाओं की जानकारी ली गई।

महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत संचालित योजनाओं, आंगनबाड़ी केंद्रों की व्यवस्था, पोषण एवं महिला-बाल कल्याण से जुड़े विषयों पर चर्चा की गई। कृषि एवं उद्यानिकी विभाग की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, किसानों को तकनीकी मार्गदर्शन एवं शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाने पर भी विचार-विमर्श किया गया।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों के निर्माण एवं रखरखाव तथा ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन की बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने से जुड़े मुद्दे भी बैठक के प्रमुख विषय रहे। जिला पंचायत उपाध्यक्ष देव नारायण यादव ने अधिकारियों से जनहित के विषयों को प्राथमिकता देते हुए योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने तथा विकास कार्यों में गुणवत्ता एवं समयबद्धता बनाए रखने की अपेक्षा की। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों की आवश्यकताओं और आमजन की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए विकास कार्यों को गति देना सभी विभागों की प्राथमिकता होनी चाहिए। बैठक में अधिकारियों ने विभागीय योजनाओं की जानकारी प्रस्तुत की तथा सदस्यों द्वारा उठाए गए विषयों पर आवश्यक जानकारी एवं सुझाव साझा किए। जिले के समग्र विकास, ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं के विस्तार तथा शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाने पर सार्थक चर्चा हुई।

जिले के 4 तहसीलदार एवं 6 नायब तहसीलदारों को किया गया इधर से उधर

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन



सूरजपुर। कलेक्टर श्रीमती रेना जमील ने राजस्व विभाग के कार्यों में कसावट लाने के उद्देश्य से जिले के तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार के मध्य पूर्व में जारी कार्य विभाजन आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए आगामी आदेश पर्यन्त प्रशासनिक व्यवस्था के दृष्टिकोण से इधर से उधर पदस्थ किया है। कलेक्टर द्वारा 18 नवम्बर को जारी आदेश के तहत तहसीलदार मो० एजाज हाशमी को प्रेमनगर, डॉ0 माधुरी आँचला को प्रेमनगर से अतिरिक्त तहसीलदार प्रतापपुर, शिवनारायण राठिया तहसीलदार भटगांव को रामानुजनगर, मनहरण राठिया तहसीलदार रामानुजनगर को भटगांव, वेतन भत्तों का आहरण संवितरण तह. सूरजपुर में अति. तह. पद के विरुद्ध होगा। श्रीमती मीना सिंह नायब तहसीलदार पिलखा को नायब तहसीलदार लिंक कोर्ट देवनगर, श्रीमती सरिता राजवाड़े नायब तहसीलदार लिंक कोर्ट देवनगर को नायब तहसीलदार सूरजपुर, श्रीमती हिना टण्डन नायब तहसीलदार संलग्न भू अभिलेख को नायब तहसीलदार भैयाथान, प्रियंका टोप्पो नायब तहसीलदार लिंक कोर्ट मानी को नायब तहसीलदार पिलखा, प्रियंका रवि नायब तहसीलदार प्रतापपुर को ना.तह. लिंक कोर्ट मानी तहसील सूरजपुर तथा मो० इजराईल खान सहा अधीक्षक भू-अभिलेख प्र० नायब तहसीलदार सूरजपुर को कार्यालय भू अभिलेख सूरजपुर में स्थानांतरित किया गया है।

राजमोहिनी देवी कृषि महाविद्यालय में उत्तर क्षेत्रीय खेलकूद प्रतियोगिता की तैयारियां तेज, अधिष्ठाता ने किया मैदान का निरीक्षण

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन



अंबिकापुर। राजमोहिनी देवी कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र, अंबिकापुर में आगामी 22 से 24 नवंबर 2026 तक आयोजित होने वाली उत्तर क्षेत्रीय अंतर-महाविद्यालयीन खेलकूद प्रतियोगिता की तैयारियां जोरों पर हैं। प्रतियोगिता के सफल आयोजन को लेकर महाविद्यालय प्रशासन ने तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में महाविद्यालय के अधिष्ठाता डॉ. एस. के. सिन्हा ने गुरुवार को खेल मैदान का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने खेल मैदान की स्थिति, पिच, ट्रैक, दर्शकों के बैठने की व्यवस्था, पेयजल, चिकित्सा सुविधा, सुरक्षा व्यवस्था और खिलाड़ियों के ठहरने सहित अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं की बारीकी से समीक्षा की। डॉ. सिन्हा ने प्रतियोगिता में होने वाली विभिन्न स्पर्धाओं के लिए मैदानों के समतलीकरण, मार्किंग, खेल सामग्री की उपलब्धता और मैदान की साफ-सफाई को लेकर संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रतियोगिता में उत्तर क्षेत्र के विभिन्न महाविद्यालयों से बड़ी संख्या में खिलाड़ी, कोच और अधिकारी शामिल होंगे, इसलिए किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहनी चाहिए। अधिष्ठाता ने कहा कि यह प्रतियोगिता विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए महत्वपूर्ण मंच है। खेलकूद से विद्यार्थियों में अनुशासन, टीम भावना, नेतृत्व क्षमता और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित होती है। महाविद्यालय का प्रयास है कि सभी प्रतिभागियों को बेहतर वातावरण और सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, ताकि वे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकें। निरीक्षण के दौरान महाविद्यालय के प्राध्यापक, खेल प्रभारी, कर्मचारी और आयोजन समिति के सदस्य उपस्थित रहे। सभी ने तैयारियों को समय पर पूर्ण करने का आश्वासन दिया।

जिला शिक्षा अधिकारी ने ली बीईओ एवं प्राचार्यों की समीक्षा बैठक

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

अम्बिकापुर। शासकीय बहुउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अम्बिकापुर के सभाकक्ष में जिला शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक हुई। इसमें सभी बीईओ, एबीईओ, शासकीय-अशासकीय हाई-हायर सेकेंडरी स्कूलों के प्राचार्य, संकुल प्राचार्य, स्वामी आत्मानंद व पीएमश्री विद्यालयों के प्राचार्य, बीआरसी और कस्तूरबा गांधी विद्यालयों की अधीक्षिकाएं उपस्थित रहीं। बैठक में आरटीई के तहत पात्र बच्चों को निःशुल्क प्रवेश दिलाने पर चर्चा हुई। मणिपुर वार्ड विद्यालय के प्राचार्य एल.पी. गुप्ता ने प्रवेश प्रक्रिया की जानकारी दी। डीईओ ने नोडल प्राचार्यों को पात्र बच्चों को चिन्हांकित कर अधिक से अधिक प्रवेश सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। पिछले वर्ष के परीक्षा परिणामों की समीक्षा कर इस वर्ष बेहतर परिणाम के लिए कार्ययोजना बनाने और यू-डाइस व अपार पंजीयन के निर्देश भी दिए गए। शासकीय विद्यालयों में नियमित प्रार्थना व मंत्रोच्चार सुनिश्चित करने और उसका वीडियो बीईओ के माध्यम से प्रस्तुत करने को कहा गया। त्रैमासिक परीक्षा में खराब प्रदर्शन वाले विद्यालयों के प्राचार्यों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। विद्यार्थियों को नियमित लेखन अभ्यास, रिवीजन कराने और नवंबर तक पाठ्यक्रम पूर्ण करने को कहा गया। लापरवाही बरतने व अनाधिकृत अवकाश पर रहने वाले शिक्षकों को नोटिस देने के निर्देश भी दिए गए।

निर्माण कार्यों की समीक्षा में स्वीकृत सभी कार्य तत्काल शुरू कराने और कोई कार्य अप्रारंभ न रखने को कहा गया। ठेकेदारों व एजेंसियों से समन्वय बनाए रखने के निर्देश दिए गए। मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता के लिए विद्यालय प्रमुखों को स्वयं जांच करने और शिक्षकों को भी भोजन ग्रहण करने को कहा गया। अनुकंपा नियुक्ति व पेंशन के लंबित प्रकरणों का तत्काल निराकरण करने और लापरवाही पर जिम्मेदारी तय कर कार्रवाई की चेतावनी दी गई।



आरटीआई 2005 के तहत पंजीयन, व्हीएसके एप में शिक्षकों-कर्मचारियों का शत-प्रतिशत पंजीयन व उपस्थिति, सेवा पुस्तिका व पासबुक का संधारण-सत्यापन, छात्रवृत्ति के लिए सभी पात्र विद्यार्थियों का पंजीयन और स्तरवार शिक्षकों की जानकारी जिला कार्यालय में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। कस्तूरबा गांधी विद्यालयों की अधीक्षिकाओं से त्रैमासिक परिणाम की समीक्षा कर बोर्ड परीक्षा के लिए बेहतर तैयारी कराने को कहा गया। सभी अधिकारियों को अधीनस्थों की गोपनीय चरित्रावली मार्च तक पूर्ण करने को कहा गया।

नीट-जेईई ऑनलाइन कोचिंग की समीक्षा में प्राचार्यों ने बताया कि यह ग्रामीण विद्यार्थियों के लिए लाभदायक है। डीईओ ने शिक्षकों व अभिभावकों से नियमित फीडबैक लेने को कहा। अंत में सभी निर्देशों का गंभीरता से पालन कर शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए समन्वित प्रयास करने के निर्देश दिए गए।

चिंतन

सोशल मीडिया न बने अश्लीलता का अड्डा

सोशल मीडिया आज संवाद, सूचना और अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है, लेकिन इसकी आड़ में परोसी जा रही अश्लीलता, हिंसा और आपत्तिजनक सामग्री ने इस मंच की उपयोगिता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए किए हैं। चिंता की बात यह है कि सोशल मीडिया कंपनियों के एल्गोरिदम कई बार ऐसी सामग्री को अधिक लोगों तक पहुंचाते हैं, जो न केवल सामाजिक मर्यादाओं को चोट पहुंचाती है, बल्कि बच्चों और किशोरों के मन-मस्तिष्क पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। ऐसे में इंस्टाग्राम का अपने कंटेंट रिकमंडेशन सिस्टम में बदलाव करना स्वागत योग्य कदम है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) की मदद से अब अश्लील और हिंसक पोस्ट को पहचान कर उन्हें यूजर्स तक पहुंचने से पहले ही रिकमंडेशन से हटाने की व्यवस्था की जा रही है। यह बदलाव केवल तकनीकी सुधार नहीं, बल्कि सोशल मीडिया की जवाबदेही तय करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण पहल है। दरअसल, सोशल मीडिया पर समस्या केवल आपत्तिजनक सामग्री अपलोड होने तक सीमित नहीं है। असली सवाल यह है कि ऐसी सामग्री को बढ़ावा कौन और कैसे देता है? प्लेटफॉर्म के एल्गोरिदम यूजर्स की रुचि और उनकी गतिविधियों के आधार पर पोस्ट सुझाते हैं। कई बार सनसनीखेज, अश्लील और हिंसक सामग्री अधिक प्रतिक्रिया जुटाती है। भारत सरकार ने 10 अक्टूबर को मेटा को इंस्टाग्राम और फेसबुक के रिकमंडेशन सिस्टम तथा एल्गोरिदम की समीक्षा करने की सलाह दी थी। इससे पहले बच्चों के यौन शोषण से जुड़े विज्ञापनों को लेकर भी मेटा को नोटिस जारी किया था। इन घटनाओं ने सोशल मीडिया कंपनियों की निगरानी व्यवस्था और जवाबदेही पर सवाल खड़े किए हैं। आखिर ऐसी सामग्री प्लेटफॉर्म तक पहुंचती कैसे है और विज्ञापन के रूप में उसका प्रसार होने से पहले उसकी जांच क्यों नहीं होती? बच्चों की सुरक्षा के मामले में किसी भी तरह की लापरवाही को सामान्य तकनीकी चूक बताकर टाला नहीं जा सकता। हालांकि, एआई आधारित फिल्टरिंग अपने आप में समस्या का संपूर्ण समाधान नहीं है। तकनीक की भी सीमाएं हैं। कई बार आपत्तिजनक सामग्री पहचानने में चूक हो सकती है, तो दूसरी ओर जागरूकता, शिक्षा या सामाजिक विमर्श से जुड़ी सामग्री भी गलत वर्गीकरण का शिकार हो सकती है। इसलिए एआई के साथ मानवीय निगरानी, पारदर्शी शिकायत निवारण और नियमित स्वतंत्र समीक्षा भी जरूरी है। कंपनियों को यह बताना चाहिए कि आपत्तिजनक सामग्री हटाने के उनके मानदंड क्या हैं और गलत तरीके से रोकी गई पोस्ट के खिलाफ यूजर कहां अपील कर सकता है। इंस्टाग्राम के नॉट इंटरेस्टेड, सेंसेटिव कंटेंट कंट्रोल और हिडन वर्ड्स जैसे विकल्पों का इस्तेमाल कर अवांछित सामग्री को सीमित किया जा सकता है। किशोरों के लिए टीन अकाउंट्स जैसी व्यवस्थाएं भी उपयोगी हैं, लेकिन इनका प्रभाव तभी होगा, जब अभिभावक बच्चों की डिजिटल गतिविधियों के प्रति सजग रहें और उनमें इंटरनेट के जिम्मेदार इस्तेमाल की समझ विकसित करें। सोशल मीडिया की स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं हो सकता कि वहां कुछ भी परोसने की छूट मिल जाए। एआई से अश्लीलता और हिंसा पर लगाम लगाने की पहल तभी सार्थक होगी, जब यह महज सरकारी निर्देश के बाद उठाया गया कदम बनकर न रह जाए, बल्कि कंपनियों की स्थायी जवाबदेही का हिस्सा बने। इसे सुरक्षित, मर्यादित और उपयोगी बनाना सरकार, कंपनियों, अभिभावकों और समाज सभी की साझा जिम्मेदारी है।



मुद्दा

प्रो.(डॉ.) मनोज दयाल

किश्तवाड़ फिर लहूलुहान..!

किश्तवाड़ में पुनः आतंकी हमला..! खूनी खेल..! एक दिन, दो हमले..! यहां के घने जंगलों में जब दो एसपीओ के शव मिले, तो पूरे देश का दिल दहल गया..! दच्छन के जंगल में दहशत : कौन मार रहा है हमारे रक्षकों को? बाँबी चंद और रशपाल कुमार - दो नाम, जो अब शहादत की अमर गाथा बन गए हैं। लेकिन यह वह भारत है, जिसने आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। यह वह भारत है, जिसने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके दुनिया को बता दिया कि अब आतंक का जवाब सिर्फ निंदा से नहीं, गोली से दिया जाएगा। 11 नवंबर को कुलगाम और किश्तवाड़ में हुई घटनाओं ने एक बार फिर साबित कर दिया कि पाकिस्तान अभी भी अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आया है। इस हमले ने मोदी सरकार के मजबूत सुरक्षा कवच को चुनौती दी है। आतंकियों ने सीधा सुरक्षा तंत्र पर हमला किया।

कुलगाम में सीआरपीएफ के नाके पर और किश्तवाड़ में एसओजी के दो एसपीओ पर, लेकिन आतंकी यह भूल गए कि भारत सरकार के रक्षा तंत्र ने सुरक्षा बलों को खुली छूट दे रखी है। आज हमारे जवानों के हाथ बंधे नहीं हैं। उन्हें पहले की तरह दिल्ली से आदेश का इंतजार नहीं करना पड़ता। भारत सरकार ने सेना, सीआरपीएफ और जम्मू-कश्मीर पुलिस को अत्याधुनिक हथियार, बुलेटप्रूफ वाहन, ड्रोन और खुफिया तंत्र दिया है। कुलगाम में हमले के कुछ ही मिनटों में पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई। किश्तवाड़ में पहले वीडीजी और अब एसपीओ की हत्या ने देश को दुखी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बार-बार कहा है कि शहीदों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद से ही आतंकियों की कमर टूट गई है। पत्थरबाजी खत्म हो गई। हड़ताल-चक्का जाम खत्म हो गया। अलगाववादियों की दुकान बंद हो गई। केंद्र सरकार की नीति है - शहीद के परिवार को नौकरी, आर्थिक सहायता और पूरा सम्मान। यही मोदी सरकार की संवेदनशीलता है। आतंकी वीडीजी और एसपीओ को इसलिए मार रहे हैं क्योंकि मोदी सरकार ने गांव-गांव में ग्राम रक्षा गार्डों को हथियार देकर स्थानीय सुरक्षा को मजबूत किया है। मोदी सरकार ने ही वीडीजी को फिर से सशक्त किया। आतंकी इसी सशक्तिकरण से घबराए हुए हैं। कुलगाम हमले के तुरंत बाद मोदी सरकार के निर्देश पर सुरक्षा एजेंसियां एक्शन मोड में आ गईं। सेना, सीआरपीएफ, पुलिस और एनआईए का संयुक्त ऑपरेशन चल रहा है। आज तलाशी अभियान में ड्रोन, थर्मल इमेजिंग, स्निफर डॉग, हेलीकॉप्टर - सब कुछ इस्तेमाल हो रहा है। यह सब मोदी सरकार के कार्यकाल में ही संभव हुआ है। पहले जहां जवानों के पास बुनियादी सुविधाएं भी नहीं थीं, आज उन्हें दुनिया के सर्वश्रेष्ठ उपकरण मिल रहे हैं। तीन संदिग्ध ओवर ग्राउंड वर्कर्स को हिरासत में लिया गया है। सीसीटीवी फुटेज की जांच हो रही है। आतंकियों का नेटवर्क धीरे-धीरे उजागर हो रहा है। मोदी सरकार की नीति स्पष्ट है - आतंकी हो या उसका मददगार, कोई नहीं बचेगा। किश्तवाड़ के 8858 फीट ऊंचे दच्छन-मरवा इलाके में भी सघन तलाशी चल रही है। मोदी सरकार ने चिनाब क्षेत्र के लिए विशेष सुरक्षा योजना बनाई है। अब हर पहाड़ी, हर जंगल में आतंकियों के छिपने की जगह नहीं बचेगी। स्थानीय नेटवर्क के



जानकारों को निशाना बनाया गया । बाँबी चंद और रशपाल कुमार स्थानीय थे। वे इलाके की हर पगडंडी जानते थे। आतंकी ऐसे ही लोगों को मारकर सुरक्षा बलों की आंख-कान को खत्म करना चाहते हैं। लेकिन भारत सरकार ने इसी को समझते हुए स्थानीय युवाओं को सुरक्षा व्यवस्था से जोड़ा है। आज जम्मू-कश्मीर पुलिस में हजारों स्थानीय युवा भर्ती हुए हैं। एसपीओ, वीडीजी, होमगार्ड-सब मोदी सरकार की स्थानीय भागीदारी की नीति का ही परिणाम हैं। मोदी सरकार ने 'विकास और विश्वास' की नीति से कश्मीर के युवाओं को मुख्यधारा से जोड़ा है। आज कश्मीर का युवा पत्थर नहीं, लैपटॉप उठा रहा है। स्टार्टअप कर रहा है। खेल में नाम कमा रहा है। आतंकियों को यही बदलाव बर्दाश्त नहीं हो रहा। इसलिए वे स्थानीय जानकारों को मारकर डर फैलाना चाहते हैं। आतंकी जहांगीर सरूर तो भारत सरकार की हिट लिस्ट पर सबसे बड़ा नाम है। किश्तवाड़ में जहांगीर सरूर उर्फ मोहम्मद अमीन का नाम तीन दशकों से चल रहा है। यह सच है कि वह लंबे समय से सक्रिय है, लेकिन यह भी सच है कि मोदी सरकार के आने के बाद ही उसके नेटवर्क को सबसे बड़ा झटका लगा है। 2018-19 में अनिल परिहार और चंदरकांत शर्मा की हत्या के बाद मोदी सरकार के निर्देश पर एनआईए ने किश्तवाड़ में बड़े पैमाने पर कार्रवाई की। उसके कई सहयोगियों - निसार अहमद शेख, निशाद अहमद, आजाद हुसैन, रुस्तम अली को गिरफ्तार किया गया। उसका नेटवर्क लगभग खत्म कर दिया गया। मोदी सरकार ने ही हिजबुल मुजाहिदीन जैसे संगठनों पर शिकंजा कसा है। उनकी फंडिंग बंद की है। हवाला नेटवर्क तोड़ा है। आज जहांगीर सरूर अकेला पड़ गया है, छिपकर घूम रहा है। सुरक्षा एजेंसियों को मोदी सरकार ने उसे पकड़ने या खत्म करने की पूरी छूट दी है। वह दिन दूर नहीं, जब उसका भी वही हश्र होगा, जो बुरहान वानी और रियाज नायकू का हुआ। आतंकियों ने अपनी नापाक चाल बदली है-छोटे हमले, स्लीपर सेल, हथियार लूटना, जीपीएस का इस्तेमाल। लेकिन भारत सरकार ने भी अपनी रणनीति बदल दी है। आज भारत सरकार की रणनीति के चार स्तंभ हैं। पहला-आतंक पर जीरो टॉलरेंस। अब आतंकियों से कोई बातचीत नहीं, सिर्फ कार्रवाई। दूसरा-सीमा पर अभेद्य सुरक्षा। एलओसी पर स्मार्ट फेंसिंग, अत्याधुनिक निगरानी और बीएसएफ को खुली छूट। घुसपैठ में 90 प्रतिशत से ज्यादा कमी आई है। तीसरा- आतंकी फंडिंग पर प्रहार। एनआईए, ईडी ने आतंकी फंडिंग के सैकड़ों मामलों में कार्रवाई की। अलगाववादी नेताओं की संपत्ति जब्त की गई। चौथा - विकास से विश्वास। भारत सरकार ने जम्मू-कश्मीर में 1 लाख करोड़ से ज्यादा की विकास योजनाएं दी हैं। आईआईटी, एम्स, सड़कें, टनल, रेल - आज कश्मीर विकास की दौड़ में है।

आतंकी स्लीपर सेल बनाते हैं, तो सरकार खुफिया तंत्र को और मजबूत करती है। आतंकी हथियार लूटते हैं, तो सरकार जवानों को और बेहतर हथियार देती है। किश्तवाड़ और कुलगाम की घटनाएं दुखद हैं, लेकिन यह अंत नहीं, आतंक के अंत की शुरुआत है। भारत सरकार ने 370 हटाया, पत्थरबाजी खत्म की, अलगाववाद खत्म किया, आतंकियों की फंडिंग बंद की। अब बचे हुए आतंकियों का भी सफाया होगा। किश्तवाड़ के विधायक शगुन परिहार ने कहा है - दो का बदला चार से लिया जाए। मोदी सरकार की नीति भी यही है - एक भी शहीद का खून बेकार नहीं जाएगा। शहीद बाँबी चंद और रशपाल कुमार के परिवारों को देश सलाम करता है। देश को विश्वास है - मोदी सरकार के नेतृत्व में किश्तवाड़ फिर उठेगा। जम्मू-कश्मीर फिर मुस्कुराएगा और आतंक का नामोनिशान मिट जाएगा, क्योंकि अब भारत डरता नहीं, भारत जवाब देता है।

(लेखक तुलजाराज ठाकरे विधि स्नातक के तृतीयवी हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

मंथन

रेणु जैन

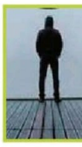


ग्रीन बिल्डिंग का बढ़ता कारवां, प्रकृति से दोस्ती

तेजी से फैलते शहरीकरण, सिकुड़ते हरित क्षेत्र, बढ़ते प्रदूषण और लगातार चढ़ते तापमान ने आज पूरी दुनिया के सामने पर्यावरण संरक्षण की गंभीर चुनौती खड़ी कर दी है। शहरों में कंक्रीट की इमारतें तो ऊंची होती जा रही हैं, लेकिन उनके बीच प्रकृति के लिए जगह लगातार कम होती जा रही है। गर्मियों में बढ़ती तपिश, एयर कंडीशनर पर निर्भरता और बिजली की खपत इस बदलते पर्यावरण की चेतावनी दे रही है। ऐसे समय में ग्रीन बिल्डिंग की अवधारणा केवल वास्तुकला का नया प्रयोग नहीं, बल्कि भविष्य के सुरक्षित और टिकाऊ शहरों की अनिवार्य आवश्यकता बनकर उभर रही है। यह आधुनिक विकास और प्रकृति के बीच संतुलन स्थापित करने की एक सार्थक पहल है। इस दिशा में केरल ने उल्लेखनीय उदाहरण प्रस्तुत किया है। यहां घरों, कार्यालयों और व्यावसायिक भवनों की छतों, बालकनियों तथा दीवारों को हरित उद्यानों में बदला जा रहा है। आम, अमरूद, पपीता, नींबू जैसे फलदार पौधों के साथ औषधीय वनस्पतियां, फूल और सजावटी पौधे इमारतों की शोभा बढ़ा रहे हैं। यह हरियाली केवल आंखों को सुकून देने तक सीमित नहीं है, बल्कि भवनों को गर्मी से बचाने में भी सहायक बन रही है। छतों पर पौधों की परत सूर्य की सीधी तपिश को कम करती है। पौधों से होने वाला वाष्पोत्सर्जन आसपास के वातावरण को ठंडा रखने में मदद करता है। परिणामस्वरूप कुछ भवनों में एयर कंडीशनर का इस्तेमाल और बिजली की खपत भी कम हो रही है। आज इसका महत्व इसलिए और बढ़ गया है, क्योंकि देश के अनेक शहर भीषण गर्मी और हीटवेव की समस्या से जूझ रहे हैं। बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों में रूफटॉप गार्डन, वर्टिकल गार्डन और हरित परिसरों के प्रति रुचि बढ़ रही है। नई इमारतों के निर्माण में प्राकृतिक रोशनी, हवा के बेहतर आवागमन, सौर ऊर्जा, वर्षा जल संचयन और अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग को महत्व दिया जा रहा है। यह बदलाव बताता है कि अब भवन निर्माण का उद्देश्य केवल सुंदर और सुविधाजनक मकान बनाना नहीं, बल्कि ऐसे परिसर तैयार करना भी है जो पर्यावरण पर कम बोझ डालें। दुनिया के अनेक देश इस सोच को व्यवहार में उतार चुके हैं। वर्तमान में ग्रीन बिल्डिंग का प्रभाव कई स्तरों पर दिखाई देने लगा है। एक ओर ये भवन ऊर्जा की खपत घटाने और वर्षा जल को संरक्षित करने में मदद कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर शहरी जैव विविधता को भी सहारा दे रहे हैं। पौधों से युक्त परिसर पक्षियों, मधुमक्खियों और तितलियों को आश्रय तथा भोजन उपलब्ध कराते हैं। हरित छतें वर्षा के पानी के बहाव को धीमा कर सकती हैं और उचित डिजाइन के साथ जलभराव का दबाव कम करने में योगदान देती हैं। धूल और कुछ वायु प्रदूषकों को रोकने में भी वनस्पतियां उपयोगी साबित होती हैं। इसका सकारात्मक असर मानव जीवन पर भी पड़ता है। हरियाली से घिरे वातावरण में रहने और काम करने वाले लोगों को मानसिक सुकून मिलता है। प्राकृतिक रोशनी, खुली हवा और पौधों की उपस्थिति तनाव कम करने तथा एकाग्रता बढ़ाने में सहायक हो सकती है। यही कारण है कि अनेक कार्यालय, अस्पताल, होटल और आवासीय परियोजनाएं अपने परिसर में हरित स्थान विकसित करने पर निवेश कर रही हैं। भारत ने वर्ष 2070 तक नेट-जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस लक्ष्य की प्राप्ति में ऊर्जा दक्ष भवनों, सौर ऊर्जा, टिकाऊ निर्माण सामग्री, जल संरक्षण और हरित वास्तुकला की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। हालांकि ग्रीन बिल्डिंग को सफल बनाने के लिए केवल छत पर पौधे लगा देना पर्याप्त नहीं है। स्थानीय जलवायु के अनुकूल पौधों का चयन, पानी की उपलब्धता, भवन की संरचनात्मक मजबूती, उचित जल निकासी और नियमित देखभाल भी जरूरी है। आज जरूरत इस बात की है कि हरियाली को विकास के बाद की व्यवस्था नहीं, बल्कि विकास की पहली शर्त माना जाए। प्रत्येक घर अपनी छत या बालकनी में कुछ पौधे लगाए, प्रत्येक कार्यालय अपने परिसर में हरित क्षेत्र विकसित करे और प्रत्येक नई इमारत पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखकर बनाई जाए। निश्चित रूप से आने वाले समय में शहरों की पहचान केवल उनकी ऊंची इमारतों, चौड़ी सड़कों और चमचमाती इमारतों से नहीं, बल्कि वहां मौजूद हरियाली और स्वच्छ वातावरण से भी होगी। ग्रीन बिल्डिंग का बढ़ता कारवां हमें यही संदेश दे रहा है कि प्रकृति से दोस्ती किए बिना विकास की कल्पना अधूरी है। यदि कंक्रीट के जंगलों में हरियाली के छोटे-छोटे द्वीप विकसित किए जाएं, तो हमारे शहर भी सांस ले सकेंगे और आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ, ठंडा तथा स्वस्थ भविष्य मिल सकेगा।

(लेखिका स्वतंत्र स्तंभकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

अहंकार ही अज्ञान है



संकलित

दर्शन

सूर्य वैसे तो सारे संसार को प्रकाश और ताप देता है, पर यदि वह मेघ से आच्छन्न हो जाए तो ऐसा नहीं कर पाता। इसी भांति जब तक हृदय अहंकार के आवरण से आच्छादित रहता है, तब तक उसमें भगवान प्रकाशित नहीं हो पाते। यह अहं मेघ की तरह है। इसी के कारण हम ईश्वर को नहीं देख पाते। यदि श्रीगुरु की कृपा से अहं-बुद्धि दूर हो जाए तो फिर ईश्वर के पूर्ण दर्शन हो जाते हैं। जैसे, सिर्फ ढाई हाथ की दूरी पर ही साक्षात पूर्णब्रह्म श्रीरामचंद्र जी हैं, किंतु बीच में सीता रूपिणी माया का आवरण होने के कारण लक्ष्मण जी रूपी जीव को ईश्वर राम के दर्शन नहीं होते। जीव का अहंकार ही माया है। यही अहंकार सब आवरण का मूल है। मैं के मरने पर ही सारा जंजाल दूर होगा। अगर किसी को ईश्वर की कृपा से मैं कर्ता नहीं हूं- यह ज्ञान हो जाए, तब तो वह जीवनमुक्त ही हो गया। फिर उसे किसी बात का भय नहीं। अगर मैं अपने को इस अंगोछे की ओट में कर लूं तो तुम मुझे नहीं देख सकते, पर मैं तुम्हारे बिल्कुल नजदीक ही हूं। इसी भांति और सभी चीजों की अपेक्षा ईश्वर ही तुम्हारे सबसे ज्यादा निकट है, किंतु अहं रूपी आवरण के कारण तुम उनके दर्शन नहीं कर सकते। जब तक अहंकार रहता है, तब तक न ज्ञान होता है, न मुक्ति मिलती है। हांडी में रखे पानी और चावल, दाल, आलू आदि को तब तक छूआ जा सकता है, जब तक हांडी आग पर नहीं रखी जाती। जीव की देह मानो हांडी है और धन, मान, विद्या, बुद्धि, जाति, कुल आदि मानों दाल, चावल, आलू की तरह हैं। अहंकार ही आग है, जिसके कारण ही जीव गरम (गर्वीला) होता है।

सुख-दुख आते-जाते रहेंगे, भक्ति नहीं छोड़नी चाहिए



संकलित

प्रेरणा

महाभारत युद्ध खत्म हो गया था। कौरव सेना खत्म हो गई थी और युधिष्ठिर राजा बन गए थे। जब पांडवों के जीवन में सब ठीक हो गया, तब श्रीकृष्ण ने सोचा कि अब मुझे द्वारिका जाना चाहिए। श्रीकृष्ण ने अपनी इच्छा पांडवों को बताई, सभी भगवान को रोकना चाहते थे, लेकिन वे नहीं रुके। श्रीकृष्ण रथ पर बैठ आगे बढ़े तो सामने कुंती खड़ी थीं। रिश्ते में कुंती श्रीकृष्ण की बुआ थीं। अपनी बुआ को देखकर श्रीकृष्ण रथ से उतरे तो कुंती ने उन्हें प्रणाम किया। ये देखकर श्रीकृष्ण बोले कि आप मेरी बुआ हैं, मेरी माता की तरह हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूं, लेकिन आज आप मुझे क्यों प्रणाम कर रही हैं? कुंती ने कहा कि कृष्ण, तुम मेरे भतीजे हो, लेकिन मैं ये भी जानती हूं कि तुम भगवान भी हो। मुझे अपना भक्त बनने दो। श्रीकृष्ण ने कहा कि ठीक है। सभी लोग भगवान से कुछ न कुछ मांगते ही हैं, आप भी कुछ मुझसे जो चाहें, वह वरदान मांग सकती हैं। कुंती ने कहा कि मुझे वरदान में दुख दे दो। वरदान में दुख की बात सुनकर श्रीकृष्ण बोले कि आप दुख क्यों चाहती हैं? आपका तो पूरा जीवन ही दुखों में बीता है। कुंती ने कहा कि दुख में तुम बहुत याद आते हो, जीवन में दुख रहेगा तो मैं तुम्हारी भक्ति करती रहूंगी। सुख के दिनों में तो मन भक्ति में लगता नहीं है। मैं हर पल तुम्हारा ही ध्यान करना चाहती हूं, इसलिए दुख मांग रही हूं। श्रीकृष्ण बोले कि ठीक है, जैसी आपकी इच्छा।

अंतर्मन

आज की पाती

पुस्तकें ज्ञानियों की समाधि हैं

पाती-मनुष्य के जीवन में पुस्तकों का महत्व केवल पढ़ने और जानकारी प्राप्त करने तक सीमित नहीं है। पुस्तकें मनुष्य के सोच को दिशा देती है,उसके व्यक्तित्व का निर्माण करती है और समाज को ज्ञान, विवेक तथा संस्कारों से समृद्ध बनाती है। पुस्तकें केवल कागज के पन्नों का संग्रह नहीं होतीं, बल्कि उनमें किसी लेखक का जीवनभर का अनुभव, चिंतन, साधना और उसकी आत्मा समाहित रहती है। किसी पुस्तक को खोलना ऐसा है, जैसे हम किसी विद्वान, विचारक या महापुरुष के साथ बैठकर संवाद कर रहे हों। इसलिए कहा गया है कि पुस्तकें ज्ञानियों की समाधि हैं। समाधि में महापुरुषों का शरीर भले ही दिखाई न दे, लेकिन उनके विचार और जीवन-दर्शन पुस्तकों के माध्यम से सदियों तक जीवित रहते हैं।

- देवपाल शर्मा, अंबाला

करंट अफेयर

ग्वाटेमाला में आपात स्थिति के बाद सुरक्षा अभियान तेज

मध्य अमेरिकी देश ग्वाटेमाला में नशीले पदार्थों की तस्करी से जुड़ी हिंसा पर रोक लगाने के लिए राष्ट्रपति बर्नार्डो अरेवालो द्वारा 30 दिनों की आपातकालीन स्थिति घोषित किए जाने के कुछ दिन बाद, सोमवार को देश के गृह और रक्षा मंत्रियों ने सुरक्षा अभियानों का निरीक्षण किया। शनिवार को घोषित इस आदेश के तहत 30 दिनों के लिए कई संवैधानिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया है। इनमें लोगों की आवाजाही और सभा करने की स्वतंत्रता भी शामिल है। इस आदेश से सुरक्षा बलों को बल प्रयोग करके भीड़ को तितर-बितर करने, लोगों को गिरफ्तार करने और बिना वारंट घरों में प्रवेश करने का अधिकार मिल गया है। गृह मंत्री मार्को एंटोनियो विलेडा ने सोमवार को कहा कि इस आपातकालीन कदम का उद्देश्य उन समूहों पर भी कार्रवाई करना है, जिनके नशीले पदार्थों की तस्करी से जुड़े होने का संदेह है और जो इस क्षेत्र में जेड (एक प्रकार का कीमती पत्थर) और सोने के अवैध खनन में शामिल हैं। विलेडा ने कहा, 'हम रक्षा मंत्रालय और सरकारी अभियोजक कार्यालय के साथ मिलकर कई योजनाबद्ध और समन्वित कार्रवाइयों कर रहे हैं। हमारे पास एक योजना है, जिसे अगले 30 दिनों में लागू किया जाएगा।'

ऑफ बीट

कसरत की थकान से उबरने में आइस बाथ है लोकप्रिय

पिछले कुछ साल में 'आइस बाथ' का चलन तेजी से बढ़ा है। दुनिया भर में खुद को स्वस्थ रखने वाले और व्यायाम करने वाले लोग इसे अपना रहे हैं, हालांकि पहले केवल एथलीट ही इसका उपयोग करते थे। 'आइस बाथ' का मतलब बर्फ के छोटे-छोटे टुकड़ों से भरे पानी में नहाना है। कसरत की थकान से उबरने के लिए 'आइस बाथ' 'आइस बाथ' लेने का मुख्य कारण मांसपेशियों में दर्द को कम करना और व्यायाम के बाद थकान से उबरना है। धावक, भारोलोलक और फुटबॉल खिलाड़ी सहित एथलीट आमतौर पर 'आइस बाथ' का उपयोग करते हैं। इस बात के पर्याप्त सबूत हैं कि 'आइस बाथ' लेने से कसरत के बाद होने वाली थकान को दूर किया जा सकता है। शोध से पता चला है कि गहन व्यायाम के तुरंत बाद 'आइस बाथ' लेने से अगले कुछ घंटे और दिनों में मांसपेशियों का दर्द कम हो सकता है। 'आइस बाथ' से मांसपेशियों की ताकत, मजबूती और लचीलेपन जैसी चीजों में मदद मिल सकती है। 'आइस बाथ' से व्यायाम के बाद होने वाली सूजन, मांसपेशियों की सूजन और मांसपेशियों की क्षति जैसी चीजों में सुधार हो सकता है। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें लगातार कई दिन तक तीव्र व्यायाम करना पड़ता है तो आपके लिए 'आइस बाथ' एक अच्छा विकल्प हो सकता है।

ट्रेंड

इमारत गिरना दुःखद

दिल्ली के शाहदरा स्थित जाफरा नगर में इमारत गिरने की दुखद घटना में हुई जान-माल की हानि अत्यंत पीड़ादायक है। इस हादसे ने जिन परिवारों से अपने अपनों को खोया है, उनके प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूँ।

- रेखा गुप्ता, सीएम, नई दिल्ली

शहादत की बरसी

महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की शहादत की बरसी पर नमन। उन्होंने अंग्रेजों के अत्याचारों के खिलाफ पूरे देश को एकजुट किया और साहस के लिए आजन्म याद किए जाएंगे।

-अरविंद केजरीवाल, पूर्व सीएम, नई दिल्ली

आउटसोर्स कर्मचारी

मध्य प्रदेश सरकार का राज्य में 3 लाख आउटसोर्स कर्मियों को नौकरी से निकालने का फैसला बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। राज्य ने पहले से ही कर्मियों की कमी है। सरकार को नई भर्तियां करनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मौजूदा कर्मियों को नौकरी से निकाल दिया जाए।

- कमलनाथ, पूर्व सीएम, मध्यप्रदेश

आस्था की बात

कभी-कभी, खासकर जब बात हमारे महाकाल लोगाथा और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर व आस्था की आती है, तो किसी गलत बात के खिलाफ आवाज उठाना, सामने वाले को उसका हिसाब देखना और उन्हें समझने में मदद करना भी जरूरी हो जाता है।

- सुनील लहरी, अभिनेता

जल जीवन मिशन की पानी की टंकी से तार चोरी करते एक गिरफ्तार

लखनऊ। जल जीवन मिशन के तहत कसमंडी कलां गांव में बनी पानी की टंकी परिसर से सोलर पैनल के तार चोरी कर रहे एक आरोपी को ग्रामीणों की मदद से पकड़ लिया गया। सूचना पर पहुंची मलिहाबाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से करीब 100 मीटर तार और चोरी में इस्तेमाल लोहे की सब्बल बरामद की है। वहीं, उसका दूसरा साथी मौके से फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक, कसमंडी कलां निवासी प्रेम कश्यप जल जीवन मिशन की पानी की टंकी पर गार्ड के पद पर तैनात हैं।

न्यायालय तहसीलदार अम्बिकापुर जिला-सरगुजा (छ०ग०)

रा०प्र०क्र०-/ब-121/2026-27

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक आनंद कुमार अग्रवाल आ०श्याम लाल अग्रवाल जाति अग्रवाल निवासी मनेन्द्रगढ रोड तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा छ०ग० के द्वारा अपने स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि ग्राम अम्बिकापुर स्थित भूमि खसरा नंबर 4551/13 रकबा 0.009 हे० भूमि एवं उस पर निर्मित मकान को अनावेदक किशोर कुमार सुराणा आ०सिद्ध करण सुराणा निवासी कुण्डला सिटी अम्बिकापुर जिला सरगुजा छ०ग० के पास अंकन राशि रुपए 52,00,000/- में बिक्री करने का सौदा तय कर बिक्री अनुमति हेतु आवेदन पत्र श्रीमान कलेक्टर महोदय सरगुजा के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, जो जांच एवं प्रतिवेदनार्थ इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है। उक्त संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति हो तो सुनवाई दिनांक 07.12.2026 के पूर्व स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि अथवा अभिषाक के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर अपना दावा-आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। समय-सीमा के बाद प्राप्त दावा-आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। आज दिनांक: 17/11/2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी।

तहसीलदार
अम्बिकापुर

न्यायालय नजूल अधिकारी अम्बिकापुर जिला सरगुजा छ०ग०

रा०प्र०क्र०-/अ-6/2026-27

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदकगण नईम अंसारी, कय्यूम अंसारी आ.स्व. जसीमुद्दीन अंसारी, सकीना बानो बेवा स्व. जसीमुद्दीन अंसारी, शहनाज बेगम बेवा स्व. नसीम अंसारी, वसीम अंसारी आ.स्व. नसीम अंसारी, सभी निवासी वार्ड नं. 36 महामाया रोड़, थो०तह० अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा के द्वारा इस आशय का आवेदन पेश किया गया है, कि आवेदकगण के पिता, पति ससुर एवं दादा जसीमुद्दीन अंसारी आ. कुर्बान शेख के स्वामित्व व अधिपत्य की नगर अम्बिकापुर, मोहल्ला परांड़ांड़ स्थित नजूल भूमि प्लॉट नं. 2484/1 रकबा 0.016 हे० भूमि है। भूधारक जसीमुद्दीन अंसारी आ. कुर्बान शेख की मृत्यु दिनांक 10.12.2008 को हो गई है एवं जसीमुद्दीन अंसारी के बड़े पुत्र मो. नसीम अंसारी की मृत्यु दिनांक 07.09.2025 को हो गई है। तद्नुपरांत उक्त भूमि से मृतक खातेदार जसीमुद्दीन अंसारी का नाम विलोपित कर फौति नामांतरण किये जाने हेतु आवेदकगण द्वारा आवेदित भूमि के मेंटनेंस खसरा एवं मृतक खातेदारों के मृत्यु प्रमाण पत्र की छायाप्रति मय दस्तावेज सहित आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 109, 110 छ.ग. भू-राजस्व संहिता 1959 के तहत प्रस्तुत किया गया है। अतः उक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति या संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो वे अपना लिखित दावा/आपत्ति स्वंय अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक-07/12/2026 तक इस न्यायालय में प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के पश्चात प्राप्त दावा/अपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। आज दिनांक 18/11/2026 को मेरे न्यायालयीन मुद्रा एंव हस्ताक्षर से जारी किया गया।

नजूल अधिकारी
अम्बिकापुर

नाम परिवर्तन सूचना

मैं मन्वती (MANYATI) (पुराना नाम, जिसे बदला जाना है) पति धर्मजीत (DHARMJEET) निवासी ग्राम-भटगांव, पोस्ट-भटगांव, थाना-भटगांव, जिला सूरजपुर (छ.ग.) ने अपना नाम मन्वती (MANYATI) (पुराना नाम) से बदल कर मानमती (MAANMATI) (नया नाम) रख लिया है। आज से मुझे मेरे नये नाम मानमती पति धर्मजीत से जाना और पहचाना जाए। सभी को सादर सूचनार्थ।

मन्वती
निवासी ग्राम-भटगांव
पोस्ट व थाना-भटगांव
जिला सूरजपुर (छ.ग.)

न्यायालय नजूल अधिकारी, अम्बिकापुर जिला-सरगुजा

रा०प्र०क्र०/अ-20(3)/2026-27

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है, कि आवेदक श्रीमती तारा अग्रहरि पति ध्यानचन्द अग्रहरि, निवासी सत्तीपारा अम्बिकापुर जिला सरगुजा छ०ग० के द्वारा शीट नम्बर-09 मोहल्ला सत्तीपारा, नगर अम्बिकापुर स्थित नजूल प्लाट नम्बर 3377/9 रकबा 1307 वर्गफीट भूमि को बैंक में बंधक रखने की अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र पेश किया गया है। उक्त भू-खण्ड के संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो अपना लिखित दावा-आपत्ति स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 30.11.2026 तक इस न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते है। नियत समय-सीमा के बाद प्राप्त दावा-आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। आज दिनांक 17.11.2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी।

नजूल अधिकारी
अम्बिकापुर

कोलंबिया यूनिवर्सिटी में राहुल के भारत की अर्थव्यवस्था वाले बयान पर भाजपा हमलावर

राहुल गांधी को बताया भारत का एक 'शातिर' 'मीर जाफर','भारत विरोधी दुष्प्रचार का नेता'

एजेंसी ▶▶ नई दिल्ली

अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर दिए गए राहुल गांधी के बयान पर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी विदेशी यात्रा पर कोलंबिया की यूनिवर्सिटी में एक साजिश के तहत भारत को बदनाम करने के लिए अनर्गल बयान, झूठे वक्तव्य और बेबुनियाद बातें कहते हैं, जिससे देश का हर नागरिक आज शर्मसार है। उन्होंने कहा कि अराजकता के प्रतीक, अपरिपक्व, भारत से नफरत करने वाले राहुल जब भी विदेशी धरती पर जाते हैं, तो झूठे बयान देते हैं। उनकी मंशा भारत की प्रगति को ठेस पहुंचाना और भारत की मजबूत अंतरराष्ट्रीय छवि को कमजोर करना है। राहुल अपरिपक्व हैं, यह हर कोई जानता है। लेकिन जब नेता प्रतिपक्ष होते हुए वे विदेशी धरती पर ऐसे जहरीले बोल बोलते हैं, तो पता चलता है कि वे भारत विरोधी हैं, एक शातिर व्यक्ति हैं और भारत के मीर जाफर हैं। जब भी संसद का सत्र होने वाला होता है, राहुल जरूर विदेशी धरती पर जाते हैं। क्या यह वे अपने विदेशी आकाओं से मार्गदर्शन प्राप्त कर सकें।

> वे विदेशों में भारत को बदनाम करने के लिए अनर्गल बयान, झूठे वक्तव्य और बेबुनियाद बातें कर रहे, गलत आरोप लगाए

◆ विपक्ष के नेता पर भाटिया ने किया हमला बाहर जहरीले बोल बोलते हैं



भारत को एक 'आर्थिक आपदा' के रूप में पेश किया

भाजपा ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर टिप्पणी को लेकर राहुल की आलोचना की और कहा कि वह 'भारत विरोधी दुष्प्रचार के नेता' हैं जो विदेशी धरती पर बार-बार देश की छवि खराब करने की कोशिश करते हैं। कई वैश्विक एजेंसियां भारत को सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक मानती है लेकिन गांधी भारत को एक 'आर्थिक आपदा' के रूप में पेश करने में जुटे हैं।

केंद्रीय मंत्री जोशी ने कहा

भारत को बदनाम करने को अपना पसंदीदा राजनीतिक शौक बना लिया

राहुल अंशकालिक नेता, हर समय निराशा फैलाने वाले व्यक्ति

केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने अर्थव्यवस्था के बारे में बयानों को लेकर राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि वे 'अंशकालिक नेता हैं, हर समय निराशा फैलाने वाले व्यक्ति हैं। राहुल जब भी विदेश यात्रा पर जाते हैं, तो उनका 'भारत विरोधी प्रचार' एक नए देश तक पहुंच जाता है। अर्थव्यवस्था को लेकर जारी अनुमानों का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि राहुल नभारत को बदनाम कर रहे।



भारत विरोधी प्रचार करने से कभी नहीं थकते

जोशी ने पोस्ट में कहा, जब भी राहुल विदेश यात्रा करते हैं, तो उनका भारत विरोधी प्रचार एक नए स्तर पर पहुंच जाता है। अंशकालिक नेता और निराशा फैलाने वाले व्यक्ति राहुल ने शेडमीं से भारत को 'आर्थिक आपदा' की ओर धकेले वाला देश बताया है।

भंडारी ने भी साधा निशाना | भारत की प्रगति और लोकतंत्र को लेकर नकारात्मक बातें की

भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने एक्स पर पोस्ट कर राहुल को 'भारत विरोधी प्रचार का नेता' बताते हुए आरोप लगाया कि वे विदेश जाकर देश की छवि खराब कर रहे हैं। भारत की प्रगति और लोकतंत्र को लेकर नकारात्मक बातें करते हैं। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है और वैश्विक स्तर पर भारतीय लोकतंत्र का सम्मान किया जाता है।



विदेशों में लोकतंत्र की आलोचना की

भंडारी ने कहा कि प्रधानमंत्री विदेश दौरों पर हमेशा भारत के राष्ट्रीय हितों और तिरंगे के सम्मान को प्राथमिकता देते हैं। उन्होंने राहुल गांधी के बयान की तुलना पीएम मोदी के व्यवहार से की।भंडारी ने एक वीडियो में दावा किया कि क्वाड जैसे अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान जमीन पर गिरा भारतीय झंडे का निशान देखकर प्रधानमंत्री ने उसे उठाकर अपनी जेब में रख लिया था। राहुल विदेश जाकर भारत की चुनावी व्यवस्था और लोकतंत्र की आलोचना करते हैं।

राहुल को नहीं दिखती आईएमएफ, मूडीज की रिपोर्ट

भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया संयोजक आशीष ऊषा अग्रवाल ने 'एक्स' पर गांधी पर विदेशी धरती पर बार- बार भारत की नकारात्मक छवि पेश करने का आरोप लगाया और कहा यही 'सिलसिला बार बार दोहराया' जा रहा है। दुनिया भारत को सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक मानती है, वहीं राहुल देश की अर्थव्यवस्था को 'आर्थिक आपदा' के रूप में पेश करने में जुटे हैं।अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और वैश्विक वित्तीय सेवा एवं जोखिम मूल्यांकन कंपनी 'मूडीज' ने भारत की आर्थिक विकास दर सात प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है।

जालंधर में नवीन का राहुल पर हमला

टूलकिट बनकर वे अराजकता फैलाना चाहते, नहीं होंगे सफल

'समरसता संकल्प यात्रा' को हरी झंडी दिखाई



एजेंसी ▶▶ जालंधर

भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने बुधवार को जालंधर में 'समरसता संकल्प यात्रा' को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब देश विकास कर रहा है, तब राहुल को आपदा दिखाई दे रही है। आप टूल किट बनकर अराजकता फैलाना चाहते हैं, लेकिन आप अपने मकसद में कभी सफल नहीं होंगे। नवीन ने पंजाब मुख्यमंत्री भगवंत मान पर निशाना साधते हुए कहा कि नशा के जरिए आपने यहां की जवानी को भटकाने का काम किया है। आपने जो नशा मुक्ति का वादा किया था वो पूरा नहीं किया है। वो केवल आपके लिए राजनीति का मुद्दा बनकर रह गया है।

मान ने पंजाब को आप का एटीएम बनाया

नवीन ने पंजाब की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि यहां कानून केवल अरविंद केजरीवाल की जेब भरने के लिए है और उनका एटीएम कराकर रख दिया है। मान सरकार ने केवल पंजाब के माफियाओं, किसानों , युवाओं को ठगने का काम किया है। पंजाब के युवाओं को बेरजोगार कर दिया है और अब पंजाब द कारोड़पति करके योजना ला रहे हैं। पंजाब के पास पैसा नहीं है और वो केवल भरमाने का काम कर रहे हैं और वेलफेयर की स्कीम की बात कर रहे हैं।

3 दिसंबर को होगा यात्रा का समापन

श्री गुरु रविदास जी की 650वीं जयंती के मौके पर नवीन 18 नवंबर को जालंधर से पार्टी की 'समरसता संकल्प यात्रा' को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह यात्रा 2,558 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और इसकी शुरुआत जालंधर-पठानकोट राजमार्ग पर डेरा सचखंड बल्लान के पास रायपुर गांव से होगी। 3 दिसंबर को वाराणसी में इसका समापन होगा। इस यात्रा का मकसद श्री गुरु रविदास जी के जीवन और उनकी शिक्षाओं को, साथ ही समानता, भक्ति, सामाजिक एकता और मानवता के उनके संदेश को लोगों तक पहुंचाना है। यह यात्रा सात राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों - पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश - के 46 शहरों से होकर गुजरेगी।

रामलीला मैदान में प्रदर्शन पर रोक की मांग

सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस

कारोबार पर असर का किया गया दावा कांग्रेस-आप से अदालत ने मांगा जवाब

एजेंसी ▶▶ नई दिल्ली

दिल्ली के रामलीला मैदान में प्रदर्शनों को रोकने की मांग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। व्यापारियों के संगठनों ने याचिका दाखिल की है। उन्होंने प्रदर्शन पर रोक लगाने की मांग की है। व्यापारियों का कहना है प्रदर्शनों से उनका कारोबार प्रभावित हो रहा है। कोर्ट ने व्यापारिक संगठनों की संशोधित याचिका पर संज्ञान लिया है। कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कांग्रेस, कॉनरोच जनता पार्टी , आम आदमी पार्टीऔर ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन को नोटिस जारी किए हैं। कोर्ट ने कहा है कि वह 27 नवंबर को प्रदर्शन के पक्ष और विरोध में दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई करेगा।

मौलिक अधिकारों के बीच संतुलन होना चाहिए



कोर्ट ने कहा कि प्रदर्शन करने के मौलिक अधिकार और कारोबार चलाने के मौलिक अधिकार के बीच संतुलन बनाना जरूरी है। वह दिल्ली और देश के दूसरे हिस्सों में हाल के प्रदर्शनों से जुड़े मामलों की अलग-अलग श्रेणियां बनाएगा। इन श्रेणियों के मामलों की

सीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन

सीजेपी, कांग्रेस, आप और आइसा हलफनामा दें

सुप्रीम कोर्ट ने सीजेपी, कांग्रेस, आप और आइसा को नोटिस जारी किया। यह नोटिस दिल्ली में पिछले महीने मुख्य दुलाव आयुक्त के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शनों को लेकर है। दिल्ली के व्यापारिक संगठनों ने याचिका दाखिल कर आरोप लगाया है।

शिवसेना नेताओं ने सोनिया की किताब का किया विरोध

शिंदे के गुट वाली शिवसेना ने जताई नाराजगी

उनके दिल में हिंदुओं के लिए नफरत किताब के पन्ने फाड़े, बोले-बैन करें

एजेंसी ▶▶ मुंबई

कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी की किताब को लेकर विवाद भी खड़ा हो गया है। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के गुट वाली शिवसेना ने किताब का विरोध किया और इस पर बैन लगाने की मांग की। मुंबई में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शिवसेना के कई नेताओं ने किताब का विरोध करते हुए इसके पन्ने फाड़ दिए। शिंदे की शिवसेना ने किताब में वीर सावरकर और बाला साहेब ठाकरे को लेकर की गई टिप्पणी पर कड़ी आपत्ति जताई और किताब में पर बैन लगाने की मांग की। शिवसेना नेताओं ने इस दौरान शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे पर भी निशाना साधा।

- मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा

शाइना ने फाड़ दी बाणा साहेब की तस्वीर



शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी की किताब 'बिलीविंगिंग' के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है। वहीं पार्टी नेता शाइना एनसी ने गलती से शिवसेना के संस्थापक बालसाहेब ठाकरे की एक तस्वीर फाड़ दी। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना और कांग्रेस ने शिवसेना संस्थापक का अपमान करने के आरोप में शाइना पर निशाना साधा है।

पेज 201 और 443 से कुछ हिस्से हटाएं

शायना एनसी, संजय निरुपम, आनंद दुबे और अन्य नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। किताब में वीर सावरकर को बदनाम किया गया है। किताब के पन्ने फाड़े, पेज 201-443 तक हटाने को कहा।

कार ने बाइक को मारी टक्कर

सरोजनीनगर, लखनऊ। सरोजनीनगर थाना क्षेत्र में करीब डेढ़ माह पहले तेज रफ्तार कार की टक्कर से हुई मोटरसाइकिल सवार युवती की मौत मामले में उसकी मां ने आरोपी वाहन चालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है।

Name Change Public Notice/Notification

This Notice is hereby issued to the general Public and all concerned Government/Private at large that I the under signed have changed my name as Nisha W/o Juber Siddqui, aged about 32 years, R/o-Ward No. 39, Rafi Kidwai Ward, Ambikapur, Thana & Tehsil-Ambikapur, Dist.-Surguja, State-Chhattisgarh (India), instead of my former Name Nisha Bharti. I should be called/known/mentioned in all records and for all the pur-poses and would henceforth be known as Nisha W/o Juber Siddique.

Old Name
NISHA BHARTI
W/o-Juber Siddqui
R/o-Ward No. 39, Rafi Kidwai Ward
Ambikapur, Tehsil-Ambikapur
Dist.-Surguja, State-Chhattisgarh (India)

New Name
NISHA
W/o-Juber Siddqui
R/o-Ward No. 39, Rafi Kidwai Ward
Ambikapur, Tehsil-Ambikapur
Dist.-Surguja, State-Chhattisgarh (India)

अशासकीय विद्यालय प्रबंधक सभा की बैठक में संगठन को मजबूत बनाने पर जोर

संवाददाता

लखनऊ। अशासकीय विद्यालय प्रबंधक सभा उत्तर प्रदेश की एक महत्वपूर्ण बैठक लखनऊ के नेहरू नगर स्थित मुख्यालय पर आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आए विद्यालय प्रबंधकों ने प्रतिभाग किया। बैठक में संगठनात्मक मजबूती, प्रबंधकों की समस्याओं के समाधान तथा संगठन के विस्तार को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में सभा के अध्यक्ष के.पी. मिश्रा के निधन के कारण रिक्त हुए अध्यक्ष पद पर सर्वसम्मति से सत्य भूषण गुप्ता (मेरठ) को अध्यक्ष चुना गया। वहीं, उपाध्यक्ष पद पर प्रांतीय कुमार श्रोत्रिय (साना), जनपद बुलंदशहर को सर्वसम्मति से जिम्मेदारी सौंपी गई। विश्व गौरव पाण्डेय को मीडिया प्रभारी नियुक्त किया गया।

अनियंत्रित डंपर दो दुकानों पर पलटा, लाखों का सामान नष्ट, दुकानदार बाल-बाल बचा

सरोजनीनगर, लखनऊ। बंथरा थाना क्षेत्र में कानपुर रोड पर बुधवार तड़के गिट्टी लदा तेज रफ्तार डंपर अचानक अनियंत्रित होकर औरावां मोड़ के पास सड़क किनारे स्थित दो दुकानों पर पलट गया। इस हादसे में दुकानदार बाल-बाल बच गया, जबकि दोनों दुकानों में रखा लाखों रुपये का सामान नष्ट हो गया। दुकान के सामने खड़ी दुकानदार की स्कूटी भी डंपर के नीचे दबकर क्षतिग्रस्त हो गई। नगर पंचायत बंथरा के चंद्रशेखरनगर वार्ड निवासी संतोष चौरसिया (30) बंथरा थाने के बगल में औरावां मोड़ पर बांस के टट्टर से बने होटल में चाय बेचने के साथ बगल में लोहे की गुमटी में पान मसाला व जनरल स्टोर की दुकान चलाते हैं।

कार्यालय कलेक्टर (आबकारी) जिला-एमसीबी(छ.ग.)

Email-excisemcb2024@gmail.com

//तृतीय निविदा सूचना//

मनेन्द्रगढ़, दिनांक 18/11/2026

सर्वसाधारण की विशेष जानकारी के लिए यह सूचना प्रकाशित की जाती है कि शासन के निर्देशानुसार पोण्डीहिल, चिरमिरी, जिला एमसीबी क्षेत्र में देशी मदिरा दुकान पोण्डीहिल हेतु एक दुकान / भवन उपयुक्त स्थल पर किराये पर लिये जाने हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक निविदाकार, निविदा शर्तों के अधीन तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा के बंद लिफाफे, एक बड़े लिफाफे में रख कर बंद लिफाफा दिनांक 25.11.2026 को दोपहर 02:30 बजे तक जमा कर सकते निर्धारित समयावधि के पश्चात प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा। तकनीकी निविदा दिनांक 25.11.2026 को सायं 04:00 बजे निविदा मूल्यांकन हेतु गठित समिति के समक्ष खोला जावेगा।

निविदा के नियम/शर्तों की जानकारी एवं निविदा प्रपत्र, जिला प्रबंधक सी.एस.एम.सी.एल. जिला-एमसीबी के पक्ष में देय रु 500/- का बैंक ड्राफ्ट, दिनांक 25.11.2026 दोपहर 11:00 बजे तक कार्यालयीन कार्यदिवस में कार्यालय जिला प्रबंधक सी.एस.एम.सी.एल. जिनी-एमसीबी में जमा कर प्राप्त कर सकते हैं।

(कलेक्टर महोदया द्वारा अनुमोदित)
प्र.जिला आबकारी अधिकारी
हेतु कलेक्टर
जिला-एमसीबी (छ.ग.)

जी 262704614/1

कार्यालय कलेक्टर (आदिवासी विकास) कोरिया, छत्तीसगढ़

-:: द्वितीय निविदा आमंत्रण सूचना ::-

क्रमांक / ESTB/23282/2026-TRIBAL KOR FRA SEC/ निर्माण / आ०वि० / 2026-27 कोरिया, दिनांक 18.11.2026

एकीकृत पंजीयन प्रणाली अंतर्गत लोक निर्माण विभाग में पंजीकृत 'द' श्रेणी या उससे ऊपर के ठेकेदारों से निम्नलिखित अनुरक्षण / लघु निर्माण कार्य हेतु अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में मुहर बन्द निविदा आमंत्रित की जाती है।

क्र	कार्य का नाम	विकास खण्ड	अनुमानित लागत (लाख में)
1	2	3	4
1	आदिवासी कन्या आश्रम बुढार में जीर्णोद्धार कार्य	बैकुण्ठपुर	3.44
2	आदिवासी कन्या आश्रम खाड़ा में जीर्णोद्धार कार्य	बैकुण्ठपुर	3.00
3	आदिवासी बालक आश्रम कटगोड़ी में जीर्णोद्धार कार्य	सोनहत	3.62
4	आदिवासी प्री.मै. बालक छात्रावास सारा में जीर्णोद्धार कार्य	बैकुण्ठपुर	3.90
5	आदिवासी प्री.मै. बालक छात्रावास सोनहत में जीर्णोद्धार कार्य	सोनहत	3.06
6	आदिवासी प्री.मै. कन्या छात्रावास बैकुण्ठपुर में जीर्णोद्धार कार्य	बैकुण्ठपुर	2.00
7	आदिवासी प्री.मै. बालक छात्रावास बैकुण्ठपुर में जीर्णोद्धार कार्य	बैकुण्ठपुर	3.67
8	अनु0जाति0 प्री.मै. कन्या छात्रावास बैकुण्ठपुर में जीर्णोद्धार कार्य	बैकुण्ठपुर	2.49
9	आदिवासी प्री.मै. बालक छात्रावास बैकुण्ठपुर में जीर्णोद्धार कार्य	बैकुण्ठपुर	1.40
	योग:-		26.58

1. निविदा हेतु आवेदन प्रस्तुत करने का दिनांक-02/12/2026 तक सायं 05:00 बजे तक
2. चालान की प्रति जमा करने का दिनांक -03/12/2026
3. निविदा प्रपत्र प्राप्त करने का दिनांक -04/12/2026
4. निविदा प्रपत्र जमा करने का दिनांक -09/12/2026
5. निविदा प्रपत्र खोलने का दिनांक-11/12/2026 दोपहर 12:00 बजे से

उपरोक्त निर्माण कार्यों की निविदा की सामान्य शर्तें, धरोहर राशि, विस्तृत निविदा विज्ञप्ति, निविदा दस्तावेज व अन्य जानकारी कार्यालयीन अवधि में सहायक आयुक्त आदिवासी विकास कोरिया, के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। निविदा प्रपत्र मूल्य सरल क्रमांक 6 एवं 9 का मूल्य 300=00 एवं शेष कार्यों का मूल्य 750=00 देय होगा।

सहायक आयुक्त
आदिवासी विकास कोरिया

जी 262704608/2

भिलाई में ई-बस का सफल ट्रायल, दुर्ग-भिलाई-रिसाली को मिलेगी बेहतर कनेक्टिविटी

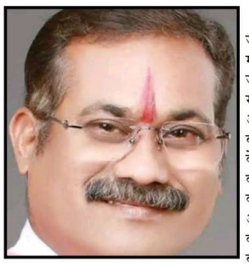
छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन



नगर। नागरिकों को सस्ती, सुलभ और सुगम यातायात सुविधा देने के लिए प्रदेश में ई-बस सेवा शुरू की जा रही है। नगर पालिक निगम भिलाई को कुल 50 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन की स्वीकृति मिली है। प्रथम चरण में 20 ई-बसें चलाई जाएंगी, इसके लिए रूट चार्ट भी तैयार कर लिया गया है। मंगलवार को निगम को ट्रायल के लिए पहली इलेक्ट्रिक बस मिली। अधिकारियों-कर्मचारियों ने इसमें सफर कर संचालन व्यवस्था और यात्रा का अनुभव लिया। ट्रायल बस नेहरू नगर चौक, सूर्या माल चौक, शंकराचार्य हॉस्पिटल, धमधा रोड, ग्रीन चौक, दुर्ग रेलवे स्टेशन रोड, दुर्ग बस स्टैंड, राजेन्द्र प्रसाद चौक, ठगड़ा बांध, पंथी चौक होते हुए रिसाली से भिलाई तक चली। ई-बस सेवा से दुर्ग, भिलाई, रायपुर, रिसाली, भिलाई चरोदा और आसपास के नागरिकों को बेहतर परिवहन मिलेगा। नौकरीपेशा, विद्यार्थियों, वरिष्ठ नागरिकों और आम यात्रियों को विशेष लाभ होगा। इलेक्ट्रिक बसों से प्रदूषण में कमी आएगी और स्वच्छ-हरित परिवहन को बढ़ावा मिलेगा। संचालन व्यवस्था समझने के लिए कलेक्टर अभिजीत सिंह और निगम आयुक्त सुरुचि सिंह दुर्ग बस स्टैंड पहुंचे और प्रधानमंत्री ई-बस सुविधाओं की जानकारी ली। ट्रायल पूरी होने के बाद निर्धारित योजना के अनुसार ई-बसों का संचालन शुरू किया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट से अमित बघेल को राहत, हेट स्पीच के सभी केसों में नियमित बेल मंजूर

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन



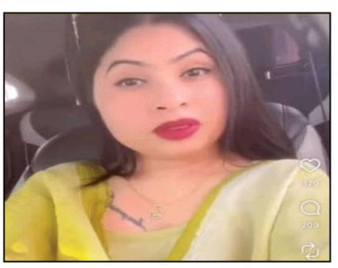
रायपुर। सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के संस्थापक एवं जोहार छत्तीसगढ़िया पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित बघेल को हेट स्पीच से जुड़े सभी 14 मामलों में नियमित जमानत दे दी है। साथ ही रायपुर जिले से बाहर रहने की शर्त भी हटा दी है। मामला 26 अक्टूबर 2025 को रायपुर के वीआईपी चौक पर छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा से तोड़फोड़ की घटना के बाद शुरू हुए विवाद से जुड़ा है। आरोप है कि इसके बाद बघेल ने अग्रवाल और सिंधी समाज के आराध्य देवताओं पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इस पर अलग-अलग थानों में कुल 14 एफआईआर दर्ज हुईं और दिसंबर 2025 में उनकी गिरफ्तारी हुई थी।

बिलासपुर हाईकोर्ट ने नियमित जमानत खारिज कर दी थी, लेकिन 3 मामलों में 3 महीने की सशर्त अंतरिम जमानत दी थी, जिसमें रायपुर से बाहर रहने की शर्त थी। यह अवधि 22 अक्टूबर 2026 को समाप्त होने के बाद उन्होंने सरेंडर किया था। हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट के 28 अक्टूबर 2026 के आदेश पर उन्होंने 11 नवंबर 2026 को आत्मसमर्पण किया था। सुनवाई में बघेल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे और अधिवक्ता हर्षवर्धन परगनिहा ने बताया कि बघेल अधिकतम 3 वर्ष की सजा वाले अपराधों में 7 माह से अधिक न्यायिक हिरासत में रह चुके हैं। राज्य शासन ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि 14 के अलावा 19 अन्य आपराधिक प्रकरणों में भी उनका आपराधिक पूर्ववृत्त है और अंतरिम जमानत की अवधि समाप्त होने के बाद भी तत्काल सरेंडर नहीं किया गया था।

सुप्रीम कोर्ट ने सभी तथ्यों पर विचार के बाद सभी 14 प्रकरणों में नियमित जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि बघेल जमानत की किसी शर्त का उल्लंघन करते हैं, तो राज्य शासन जमानत निरस्त कराने के लिए आवेदन दे सकता है।

वायरल वीडियो को लेकर सिविल सोसायटी में आक्रोश, मधुबाला गिरी के खिलाफ कार्रवाई की मांग

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन



रायपुर। छत्तीसगढ़िया समाज के खिलाफ सोशल मीडिया पर कथित आपत्तिजनक और अपमानजनक टिप्पणी का मामला सामने आया है। मधुबाला गिरी नामक महिला के वायरल वीडियो को लेकर छत्तीसगढ़ सिविल सोसायटी ने कड़ी नाराजगी जताई है। संगठन ने पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन सौंपकर महिला के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की कड़ी और गैर-जमानती धाराओं के तहत कार्रवाई की मांग की है। आरोप है कि वीडियो में छत्तीसगढ़िया समाज के लिए अशोभनीय शब्दों का इस्तेमाल करने के साथ खुलेआम धमकियां भी दी गई हैं, जिससे लोगों की भावनाओं और आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है।

सिविल सोसायटी के संयोजक डॉ. कुलदीप सोलंकी ने ज्ञापन में बताया कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में मधुबाला गिरी कथित तौर पर छत्तीसगढ़िया समाज के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करती दिख रही हैं। संगठन के अनुसार वीडियो में समाज के लोगों को ह्रजाहिल-गंवारह्व और ह्रअनपढ़ह्व जैसे शब्दों से संबोधित किया गया। साथ ही ह्रछह्व नंबर की चप्पल का निशान गाल पर पड़ेगाह्व और ह्रसामने आने पर पैंट गीली हो जाएगीह्व जैसी धमकी भरी बातें कहे जाने का भी उल्लेख है। संगठन ने इन शब्दों को उकसावे वाला और आपराधिक अभित्रास की श्रेणी का बताया है।

सोलंकी का कहना है कि किसी समाज को सामूहिक रूप से अपमानित करना गंभीर चिंता का विषय है। छत्तीसगढ़िया समाज अपनी संस्कृति, परंपरा और पहचान के प्रति संवेदनशील है, इसलिए ऐसे शब्दों से आत्मसम्मान को गहरी ठेस पहुंची है। संगठन ने आशंका जताई है कि ऐसे बयान समाज के वर्गों के बीच तनाव और कटुता पैदा कर सकते हैं और रायपुर सहित प्रदेश में सामाजिक सौहार्द प्रभावित हो सकता है। सार्वजनिक मंचों पर किसी समुदाय के खिलाफ अपमानजनक और धमकी भरी भाषा कानून-व्यवस्था के लिए चुनौती है। सिविल सोसायटी ने वायरल वीडियो की जांच कर कठोर धाराओं में कार्रवाई की मांग की है। हालांकि कौन सी धाराएं लागू होंगी, यह जांच के बाद तय होगा। वायरल वीडियो की प्रामाणिकता और आरोपों की आधिकारिक जांच के निष्कर्ष अभी उपलब्ध नहीं हैं। अब देखना होगा कि शिकायत पर पुलिस क्या कार्रवाई करती है।

भारत मंडपम में गूंजेगी छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति, 7 पारंपरिक नृत्यों की होगी प्रस्तुति

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन



रायपुर। 45वें भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में शुक्रवार, 20 नवंबर को शाम 5 बजे भारत मंडपम नई दिल्ली के एम्फी थिएटर-01 में छत्तीसगढ़ राज्य दिवस समारोह मनाया जाएगा। इसमें राज्यपाल रमेन डेका मुख्य अतिथि होंगे और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय अध्यक्षता करेंगे। समारोह में प्रदेश के लोक कलाकार गौर नृत्य, गौरा-गौरी, भोजली, राउत नाचा, सुआ, पंथी और करमा - इन 7 पारंपरिक नृत्यों से जनजातीय जीवन, लोक आस्था, सामाजिक परंपरा और ग्रामीण संस्कृति की झलक प्रस्तुत करेंगे। गौर नृत्य बस्तर की जनजातीय परंपरा, राउत नाचा यादव समाज की पहचान, सुआ महिलाओं की सामूहिक अभिव्यक्ति, पंथी सतनाम पंथ की आध्यात्मिक परंपरा और करमा सामूहिक उल्लास का प्रतीक है

कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद, विधायक और निगम-मंडल अध्यक्ष सहित कई विशिष्ट अतिथि रहेंगे। आयोजन संस्कृति एवं राजभाषा विभाग द्वारा किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य लोक कलाओं को राष्ट्रीय पहचान दिलाना है। वहीं छत्तीसगढ़ पवेलियन भी आकर्षण का केंद्र है। यहां बस्तर की बेलमेटल कला, जनजातीय आभूषण, हस्तशिल्प, चांपा की कोसा सिल्क, हथकरघा वस्त्र, हर्बल उत्पाद, कोदो-कुटकी-रागी जैसे मिलेट उत्पाद, चित्रकोट जलप्रपात का 3डी वर्चुअल रियलिटी अनुभव और स्थानीय उद्यमियों-स्टार्टअप के नवाचार प्रदर्शित किए जा रहे हैं।

सीजीबीएसई की परीक्षा का टाइम टेबल हुआ जारी, 12 मार्च से शुरू होंगे 12वीं के एग्जाम

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन



रायपुर। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल (सीजीबीएसई) ने वर्ष 2027 की हाईस्कूल और हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षाओं की समय-सारणी जारी कर दी है। कक्षा 12वीं की परीक्षाएं 12 मार्च से 8 अप्रैल और कक्षा 10वीं की परीक्षाएं 13 मार्च से 5 अप्रैल 2027 तक होंगी। दोनों कक्षाओं के पेपर सुबह 9 बजे से दोपहर 12:15 बजे तक चलेंगे।

12वीं की परीक्षा

12 मार्च को हिंदी, 15 मार्च को राजनीति विज्ञान, रसायन शास्त्र, लेखाशास्त्र, 17 मार्च को संस्कृत, 19 मार्च को जीव विज्ञान और अर्थशास्त्र, 24 मार्च को समाजशास्त्र, 29 मार्च को गणित, 31 मार्च को अंग्रेजी, 3 अप्रैल को इतिहास, व्यवसाय अध्ययन, कृषि विज्ञान, ड्राइंग एंड पेंटिंग, आहार एवं पोषण, 5 अप्रैल को भूगोल और भौतिक शास्त्र, 6 अप्रैल को व्यावसायिक पाठ्यक्रम, 7 अप्रैल को क्षेत्रीय एवं अन्य भाषाएं और 8 अप्रैल को मनोविज्ञान का पेपर होगा।

10वीं की परीक्षा

13 मार्च को तृतीय भाषा (संस्कृत, मराठी, उर्दू, पंजाबी, सिंधी, बंगाली, गुजराती, तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़, उड़िया), 16 मार्च को अंग्रेजी, 18 मार्च को सामाजिक विज्ञान, 20 मार्च को विज्ञान, 25 मार्च को हिंदी, 30 मार्च को गणित, 1 अप्रैल को व्यावसायिक पाठ्यक्रम और 5 अप्रैल को दृष्टिबाधितों के लिए संगीत और मूक-बधिरों के लिए ड्राइंग एंड पेंटिंग का पेपर होगा।

परीक्षा केंद्र पर 9 बजे पहुंचना अनिवार्य

परीक्षार्थियों को सुबह 9 बजे तक केंद्र में पहुंचना होगा। 9:05 बजे उत्तरपुस्तिकाएं और 9:10 बजे प्रश्नपत्र मिलेंगे। 9:15 बजे से 12:15 बजे तक उत्तर लिखने का समय मिलेगा। शारीरिक प्रशिक्षण पत्रोपाधि परीक्षा प्रथम वर्ष की परीक्षाएं 12 से 19 मार्च और द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं 13 से 20 मार्च तक होंगी। मंडल ने कहा है कि जरूरत पड़ने पर तिथियों में बदलाव हो सकता है। परीक्षा अवधि में अवकाश घोषित होने पर भी परीक्षाएं निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होंगी। विस्तृत समय-सारणी वेबसाइट ६६६.री.ल्ल्रू.ल्ल पर देखी जा सकती है।

मुख्यमंत्री ने ऑडिट पखवाड़ा 2026 का किया शुभारंभ

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन



रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गुरुवार को राजधानी रायपुर में ऑडिट पखवाड़ा 2026 का शुभारंभ किया। समारोह में शामिल होने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पखवाड़े के दौरान विभिन्न विषयों पर कार्यक्रम आयोजित होंगे, जिनमें कई विशेषज्ञ शामिल होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि विशेषज्ञों के अनुभव और सुझावों से जनता के पैसे का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। ऑडिट जैसी व्यवस्थाएं वित्तीय कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करती हैं। इससे सार्वजनिक धन के सदुपयोग और वित्तीय कार्यप्रणाली को बेहतर बनाने में सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि ऑडिट का मुख्य उद्देश्य वित्तीय लेनदेन, व्यय और अभिलेखों की जांच के माध्यम से नियमों और प्रक्रियाओं के अनुपालन का आकलन करना है। सरकारी वित्तीय व्यवस्था में ऑडिट के माध्यम से संसाधनों के उपयोग की समीक्षा होती है और सुधार की संभावनाओं की पहचान होती है। मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि पखवाड़े में विशेषज्ञों की सहभागिता और विभिन्न कार्यक्रमों से जनता के धन के सदुपयोग के प्रयासों को नई दिशा मिलेगी और वित्तीय व्यवस्थाओं को मजबूत बनाने में सहायता मिलेगी।

राज्यपाल से आईआईएमयूएन की चार्ज डी अफेयर्स अंबर फातिमा ने की सौजन्य भेंट

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन



रायपुर। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका से बुधवार को राजभवन में इंडिया इंटरनेशनल मूवमेंट टू यूनाइट नेशंस (आईआईएमयूएन) की चार्ज डी अफेयर्स सुश्री अंबर फातिमा ने सौजन्य भेंट की। भेंट के दौरान सुश्री फातिमा ने राज्यपाल को संस्था की गतिविधियों, उद्देश्यों और युवाओं के बीच चल रहे विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आईआईएमयूएन देशभर में युवाओं में नेतृत्व क्षमता, संवाद कौशल, आत्मविश्वास और वैश्विक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए निरंतर कार्य कर रहा है। संस्था के माध्यम से विद्यार्थियों को संयुक्त राष्ट्र की कार्यप्रणाली, अंतरराष्ट्रीय मुद्दों, कूटनीति और जनहित के विषयों पर चर्चा, वाद-विवाद और मॉक सत्रों के जरिए व्यावहारिक अनुभव प्रदान किया जाता है।

सुश्री फातिमा ने राज्यपाल को आगामी माह बिलासपुर में प्रस्तावित यूथ कनेक्ट कार्यक्रम की रूपरेखा से भी अवगत कराया। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में विद्यार्थी और युवा प्रतिभागी शामिल होंगे। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को नेतृत्व, संवाद, टीम वर्क और सामाजिक सरोकारों के प्रति जागरूक करना है। इस अवसर पर सुश्री फातिमा ने राज्यपाल रमेन डेका को बिलासपुर में आयोजित होने वाले यूथ कनेक्ट कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होने के लिए औपचारिक रूप से आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि राज्यपाल की उपस्थिति और मार्गदर्शन से युवाओं को प्रेरणा मिलेगी और कार्यक्रम की सार्थकता और बढ़ेगी। राज्यपाल ने आईआईएमयूएन के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि युवाओं में नेतृत्व क्षमता और वैश्विक सोच विकसित करने वाले इस तरह के कार्यक्रम समय की आवश्यकता हैं। उन्होंने कहा कि आज का युवा ही कल का भारत है, इसलिए उसे सही दिशा, संस्कार और मंच देना बेहद जरूरी है। उन्होंने संस्था के आगामी कार्यक्रमों के लिए शुभकामनाएं भी दीं।

सड़क निर्माण में 19.17 करोड़ की अनियमितता मे 13 अधिकारी निलंबित

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन



रायपुर। बीजापुर में पीएमजीएसवाई की 24 सड़कों की जांच में 19.17 करोड़ रुपये के अतिरिक्त भुगतान का खुलासा हुआ है। सरकार ने 3 कार्यपालन अभियंता, 6 सहायक अभियंता और 4 उप अभियंता समेत 13 अधिकारियों को निलंबित कर विभागीय जांच शुरू की है। 5 सेवानिवृत्त अधिकारियों पर भी कार्रवाई हो रही है। उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि पोर्टल पर 218 किमी मिट्टी का काम दर्ज था, जबकि मौके पर मात्र 116 किमी काम मिला। कई जगह निर्माण स्तरहीन था। अधूरी सड़कों को पोर्टल पर पूर्ण दिखाकर भुगतान किया गया और गलत जानकारी से केंद्र को भी भ्रमित किया गया। जांच में गुदमा-आरामंगी, पोकरम-दुडुम, चेरपाल-पदमुर, गुडनगुर, एनएच-16-कांदुलनार, पडेडा-पेड्डाकोरमा, बासागुड़ा-दल्ला, गलगम, लिंगागिरी, तिम्मापुर-रेखापल्ली, बार सूर पल्ली-गदियापारा, आवापल्ली-कोटापल्ली सहित 24 सड़कें शामिल हैं। पहले 25 अधिकारियों-कर्मचारियों को नोटिस दिए गए थे। निलंबितों में ईई सुरेश कुमार नागेश, बीएस ठाकुर, जितेंद्र मेश्राम, एई एसके बांधे, मुविश लहरे, सतानंद महिकवार, हेमंत सालेचा, सोमकांत साहू, चंद्रकांत भगत और एसडीओ गिरधर लहरी, यशवंत साहू, लोकेश सोनी, तस्वीर गोंड हैं। सेवानिवृत्त ईई के.आर. शास्त्री, आर.के. साहू, एम.पी. खरे, विजय कोमरे, पी.एम. साहू भी घेरे में हैं। 15 ठेकेदारों को वसूली नोटिस दिए गए थे। 5 ठेकेदारों से 5.50 करोड़ की वसूली की प्रक्रिया चल रही है। राशि जमा नहीं करने पर एफआईआर के निर्देश हैं। अधूरी सड़कों के लिए बीजापुर की 45 और सुकमा की 23 सड़कों का री-टेंडर होगा। बस्तर की 148 अधूरी सड़कों को 31 मार्च 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य है। निगरानी के लिए 5 अधीक्षण अभियंता लगाए गए हैं।

प्रकरणों के निराकरण में बर्दाश्त नहीं विलंब एवं लापरवाही : पटेल

पुलिस अधीक्षक ने क्राइम मीटिंग में दिए आवश्यक व सख्त निर्देश

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

सूरजपुर। यहां जिला पुलिस कार्यालय में बुधवार को पुलिस अधीक्षक योगेश कुमार पटेल के द्वारा जिले के पुलिस राजपत्रित अधिकारियों, थाना-चौकी एवं विभिन्न शाखाओं के प्रभारियों की क्राइम मीटिंग ली गई। बैठक में पूर्व में जारी निर्देशों के पालन की समीक्षा के साथ जिले में अपराध नियंत्रण, लंबित प्रकरणों के शीघ्र निराकरण, कानून-व्यवस्था की स्थिति एवं आधुनिक तकनीक आधारित पुलिसिंग को और अधिक प्रभावी बनाने के संबंध में विस्तृत समीक्षा की गई। पुलिस अधीक्षक ने प्रत्येक थाना-चौकी प्रभारी से अपराधों की विवेचना, लंबित प्रकरणों, चालान, मर्ग, गुम इंसान, शिकायतों की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने प्रकरणों के लंबित रहने के कारणों की समीक्षा करते हुए स्पष्ट निर्देश दिए कि प्रत्येक प्रकरण का निराकरण निर्धारित समय-सीमा में सुनिश्चित किया जाए तथा किसी भी स्तर पर अनावश्यक विलंब अथवा लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रभावी पुलिसिंग का आधार अपराधों की रोकथाम, त्वरित कार्यवाही, गुणवत्तापूर्ण विवेचना, आधुनिक तकनीक का बेहतर उपयोग तथा आमजन के प्रति संवेदनशील व्यवहार है। सभी थाना एवं चौकी प्रभारी आम नागरिकों की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए उनका तत्परता एवं प्राथमिकता के साथ निराकरण करें। पुलिस अधीक्षक ने 60 एवं 90 दिवस से अधिक समय से लंबित अपराधों को गंभीरता से लेते हुए इनके शीघ्र निराकरण को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रत्येक प्रकरण में विवेचना की प्रगति, साक्ष्यों के



संकलन, आरोपियों की गिरफ्तारी एवं चालान प्रस्तुत करने की स्थिति की समीक्षा करते हुए विवेचकों को गुणवत्तापूर्ण, निष्पक्ष एवं वैज्ञानिक साक्ष्यों पर आधारित विवेचना करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही ई-साक्ष्य सिड, आईआईएफ-1 से 6 तक की प्रविष्टियों तथा कैस एंट्री पेडिंग चार्जशीट की स्थिति का भी परीक्षण किया गया। सभी संबंधित अधिकारियों को लंबित डिजिटल प्रविष्टियों एवं अभिलेखीय कार्यों को प्राथमिकता से पूर्ण कर रिकॉर्ड अद्यतन रखने के निर्देश दिए। बैठक में फरार आरोपियों की गिरफ्तारी, समंस एवं वारंटों की तामीली, निगरानी बदमाशों एवं गुंडा बदमाशों की गतिविधियों की समीक्षा की गई। सभी थाना व चौकी प्रभारियों को फरार आरोपियों एवं वारंटियों की पतासाजी कर उनकी शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित करने तथा आदतन अपराधियों पर सतत निगरानी रखने के निर्देश दिए गए। कानून-व्यवस्था प्रभावित करने वाले तत्वों के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई एवं जिलाबदर हेतु चिन्हांकित अपराधियों के विरुद्ध नियमानुसार प्रभावी कार्यवाही करने पर भी जोर दिया गया। बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक योगेश देवांगन, सीएसपी विशाल गर्ग, एसडीओपी प्रेमनगर बेर्नार्ड कुजूर, एसडीओपी सूरजपुर अभिषेक पैंकरा, डीएसपी अजाक रीता नीलम कुजूर, जिले के थाना-चौकी प्रभारी सहित जिला पुलिस कार्यालय के अधिकारीगण मौजूद रहे। पुलिस अधीक्षक ने सभी थाना-चौकी प्रभारियों को अपने-अपने क्षेत्र में मादक पदार्थों के अवैध कारोबार एवं नशा तस्करी के विरुद्ध निरंतर प्रभावी एवं कठोर वैधानिक कार्यवाही करने के कड़े निर्देश दिए। नशे के अवैध कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों के साथ उनके नेटवर्क की पहचान कर ठोस एवं परिणाममूलक कार्यवाही सुनिश्चित करने को कहा। बीट प्रणाली को पूरी तरह सक्रिय एवं प्रभावी बनाने पर विशेष जोर देते हुए निर्देशित किया कि बीट अधिकारी नियमित रूप से अपने क्षेत्रों में भ्रमण करें, आम नागरिकों से निरंतर संपर्क एवं समन्वय बनाए रखें तथा क्षेत्र के संदिग्ध व्यक्तियों, आपराधिक गतिविधियों एवं संवेदनशील स्थानों की अद्यतन जानकारी संकलित करें। थाना-चौकी प्रभारी स्वयं इन गतिविधियों की मॉनिटरिंग करें, ताकि अपराधों की रोकथाम के साथ क्षेत्र में शांति एवं कानून-व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। एसपी ने कहा कि अपने अपने क्षेत्रों में यातायात नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराएं। शराब के नशे में वाहन चलाने तथा लापरवाहीपूर्वक एवं तेज गति से वाहन चलाने वाले चालकों के विरुद्ध सघन जांच अभियान चलाकर प्रभावी वैधानिक कार्यवाही करें। साथ ही राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गों पर अनाधिकृत रूप से वाहन खड़ा करने वालों के विरुद्ध सख्ती बरते ताकि दुर्घटनाओं की रोकथाम के साथ-साथ यातायात का सुचारू एवं सुरक्षित संचालन बना रहे। आधुनिक तकनीक को प्रभावी पुलिसिंग एवं वैज्ञानिक विवेचना का महत्वपूर्ण आधार बताते हुए एसपी श्री पटेल ने सीसीटीएनएस, ई-साईन चालान, ई-साक्ष्य, ई-मेडलीपीआर, ई-एफएसएल सहित विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने सभी अधिकारियों एवं विवेचकों को इन प्लेटफॉर्म का नियमित एवं प्रभावी उपयोग, ई मेडलीपीआर के प्रभावी क्रियान्वयन तथा सभी विवेचकों द्वारा नियमित सीआरए लॉगिन सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। एसपी ने स्पष्ट किया कि डिजिटल कार्यों एवं ऑनलाइन प्रविष्टियों में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी तथा सभी आवश्यक प्रविष्टियां निर्धारित समय-सीमा में त्रुटिरहित पूर्ण की जाएं। थानों में लंबित जप्ती माल का नियमानुसार शीघ्र निराकरण सुनिश्चित करने, प्रकरणों में जप्त वाहनों, मादक पदार्थों, अवैध सामग्रियों एवं अन्य संपत्ति का वर्षवार विवरण तैयार कर आवश्यक वैधानिक प्रक्रिया पूर्ण करने के निर्देश दिए। न्यायालय में लंबित मामलों में प्रभावी पैरवी एवं समन्वय स्थापित कर जप्ती माल के निराकरण में अनावश्यक विलंब न होने दें। साथ ही जप्ती माल के रखरखाव एवं अभिलेखों का व्यवस्थित संधारण सुनिश्चित करने निर्देशित किया।

सोलर प्लांट ऑपरेटरों को 15 महीने से नहीं मिला मानदेय, आर्थिक तंगी से जूझ रहे कर्मचारी

पहाड़ी अंचल के दो दर्जन गांवों में सोलर प्लांट के संचालन पर उठे सवाल



प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

चांदनी बिहारपुर। सूरजपुर जिले के ओड़गी विकासखंड अंतर्गत चांदनी बिहारपुर के पहाड़ी अंचल में बिजली की समस्या दूर करने के उद्देश्य से क्रेडा विभाग द्वारा करीब दो दर्जन गांवों में सोलर पावर प्लांट स्थापित किए गए हैं। इन सोलर प्लांटों के माध्यम से ग्रामीणों को बिजली सुविधा उपलब्ध कराने तथा प्लांट के नियमित संचालन के लिए विभाग द्वारा ऑपरेटरों की नियुक्ति की गई थी। लेकिन विभागीय व्यवस्था की विडंबना देखिए कि गांवों में सोलर प्लांट को चालू और बंद करने की जिम्मेदारी संभालने वाले ऑपरेटरों को पिछले 15 महीनों से मानदेय का भुगतान नहीं किया गया है। लंबे समय से मेहनताना नहीं मिलने के कारण ऑपरेटर आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे हैं।

जानकारी के अनुसार, क्रेडा विभाग द्वारा पहाड़ी एवं दूरस्थ अंचल के गांवों में बिजली की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सोलर पावर प्लांट लगाए गए थे। इन प्लांटों के संचालन, नियमित रूप से चालू-बंद करने और बिजली व्यवस्था बनाए रखने के लिए स्थानीय स्तर पर ऑपरेटर रखे गए थे। शुरुआत में ऑपरेटरों को प्रत्येक महीने उनके कार्य के एवज में निर्धारित मजदूरी का भुगतान किया जाता था। इससे वे नियमित रूप से अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे, लेकिन पिछले 15 महीने से भुगतान नहीं होने के कारण उनके सामने परिवार का भरण-पोषण और रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने की समस्या खड़ी हो गई है। ग्रामीणों का कहना है कि चांदनी बिहारपुर क्षेत्र का पहाड़ी अंचल होने के कारण कई गांव आज भी बिजली की नियमित सुविधा के लिए सोलर पावर प्लांट पर निर्भर हैं। इसी समस्या को देखते हुए क्रेडा विभाग द्वारा गांवों में सोलर प्लांट स्थापित कर ऑपरेटरों की व्यवस्था की गई थी, ताकि समय पर प्लांट चालू और बंद हो तथा ग्रामीणों को बिजली मिलती रहे। लेकिन जब ऑपरेटरों को ही लंबे समय से मानदेय नहीं मिल रहा है तो ऐसे में व्यवस्था का नियमित संचालन भी प्रभावित होने की आशंका बनी हुई है। ग्रामीणों का कहना है कि योजना के संचालन के लिए जिम्मेदार विभाग को ऑपरेटरों की समस्याओं पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। शासन की मंशा थी कि पहाड़ी अंचल के दूरस्थ गांवों में सोलर बिजली के माध्यम से लोगों को राहत मिले और ग्रामीणों को अंधेरे में रहने की मजबूरी से छुटकारा मिल सके। इसके लिए लाखों रुपये खर्च कर सोलर पावर प्लांट स्थापित किए गए तथा उनके संचालन के लिए ऑपरेटर भी रखे गए। लेकिन मानदेय नहीं मिलने का मामला विभागीय कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहा है। एक ओर ऑपरेटर अपनी जिम्मेदारी निभाने के बावजूद भुगतान के इंतजार में हैं, वहीं दूसरी ओर ग्रामीणों को भी सोलर बिजली व्यवस्था के सुचारू संचालन की चिंता सता रही है।

कलेक्टर से जांच व बकाया भुगतान कराने की मांग

मामले को लेकर क्षेत्र के ग्रामीणों ने सूरजपुर कलेक्टर से हस्तक्षेप करने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि क्रेडा विभाग द्वारा नियुक्त ऑपरेटरों के पिछले 15 महीनों के बकाया मानदेय की जांच कर तत्काल भुगतान कराया जाए। साथ ही सोलर पावर प्लांटों की वर्तमान स्थिति की भी गांववार जांच कराई जाए, ताकि यह पता चल सके कि कितने प्लांट नियमित रूप से संचालित हैं और कितने बंद पड़े हैं। ग्रामीणों ने मांग की है कि जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय करते हुए लापरवाही पाए जाने पर उचित कार्रवाई की जाए, जिससे पहाड़ी अंचल के गांवों में सोलर बिजली व्यवस्था सुचारू हो सके और ऑपरेटरों को भी उनके कार्य का मेहनताना समय पर मिल सके।

14 सूत्रीय मांगों को लेकर आंबा कार्यकर्ताओ ने निकाली रैली, सौपा ज्ञापन, आंबा कार्यकर्ताओ का तीन दिवसीय धरना समाप्त

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

सूरजपुर। 14 सूत्रीय मांगों को लेकर जुझारू आगनबाड़ी कार्यकर्ता एंव सहायिका कल्याण संघ के बैनर तले आंगन बाड़ी कार्यकर्ताओ का आज तीन दिवसीय धरना समाप्त हो गया।कार्यकताओं ने इस बीच सरकार के ध्यानाकर्षण के लिए अनेक तरह के रास्ते अपनाए हैं।संघ ने कहा है कि लगातार जिले के समस्याओं एवं मांगों के लिए ज्ञापन देते आऐं है। किंतु आज उपरांत हमारी किसी मांगों की पूर्ति एवं समस्या का निराकरण नहीं किया गया हैं। मांगे पूरी नही हुई तो 11,12 दिसंबर को दो दिवसीय प्रांतस्तरीय महापडाव किया जायेगा। उक्त ध्यानाकर्षण धरना प्रदर्शन के बाद भी मांगो की पूर्ति नहीं होती है तो प्रदेश की आंगनबाडी कार्यकर्ता अनिस्चित कालीन हड़ताल में जाने हेतु मजबूर होंगे। संघ ने नियमितिकरण करने, नियमितिकरण करते तक कार्यकर्ता, सहायिकाओं को 30 हजार रूपये मानदेय देने आयु सीमा में छूट प्रदान कर कार्यकर्ताओं को 200 से



अधिक रिक्त पर्यवेक्षक पदों में परीक्षा ना लेकर तत्काल 50क्ष में पदोन्नत करने,सेवा समाप्ति के बाद कार्यकर्ता, सहायिकाओं को 10 लाख की एकमुस्त राशि देने, पोषण ट्रेकर एवं अन्य एप में कार्य करने हेतु उच्च गुणवतायुक्त 5 जी मोबाईल दिया जाऐ एवं वर्तमान में दी जा रही नेट खर्च में वृद्ध कर 500 रू. प्रति माह करने सहित कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं को प्रदत्त मानदेय में हो रही गड़बडी को तत्काल सुधार करने, आंगनबाड़ी के बच्चों को यूनिफार्म देने, आगंनबाड़ी में टीवी, पंखा, कुलर की व्यवस्था करने,जर्जर भवनों का तत्काल नवीनीकरण करने,प्रत्येक आंगनबाड़ी के बच्चो को पर्याप्त खिलौना दिया जाऐ एवं जनप्रतिनिधियो या अन्य से मांगने हेतु न कहने,मुनगा एप में कार्य में कार्य ना लिए जाने,पूरक पोषण आहार में दिया जा रहा रेडीटूईट को परिवर्तन कर उच्च गुणवत्ता युक्त पोषण आहार देने,गर्म भोजन का चांवल माईस में जा रहा है जिसकी बचत की जानकारी देने,महतारी वंदन कार्य का प्रोत्सान राशि दी जाये अन्यथा इसमें कार्य न लिए जाने की मांग की है।

जल संरक्षण कार्यों का जायजा लेने पहुंची केंद्रीय टीम ने की सराहना

जल संचय जनभागीदारी अभियान 2.0 में प्रदेश में प्रथम और देश में चौथा स्थान पर है सूरजपुर

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

सूरजपुर। जल संरक्षण, संवर्धन एवं प्रभावी जल प्रबंधन की दिशा में किए जा रहे उल्लेखनीय कार्यों से जिला राष्ट्रीय स्तर पर अपनी विशिष्ट पहचान बना रहा है। भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा आयोजित 7 वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार के लिए जिले की दावेदारी के तहत दो सदस्यीय केंद्रीय निरीक्षण दल ने जिले का दौरा कर विभिन्न जल संरक्षण संरचनाओं एवं उनसे जुड़ी आजीविका गतिविधियों का भौतिक सत्यापन किया। इस दौरान केंद्रीय टीम ने जिले में वर्षा जल संचयन, भू-जल पुनर्भरण एवं जल संसाधनों के प्रभावी उपयोग के लिए किए गए कार्यों की सराहना की। राष्ट्रीय जल पुरस्कार के लिए स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा शॉर्टलिस्ट किए जाने के पश्चात केंद्रीय टीम ने जिले में पहुंचकर जल संरक्षण कार्यों की जमीनी हकीकत परखी। निरीक्षण दल में भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय से भारतीय इंजीनियरिंग सेवा के उप संचालक घनश्याम पटेल एवं सहायक संचालक धीरज कुमार हंस शामिल रहे। केंद्रीय टीम की सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर निर्णायक समिति द्वारा अंतिम विजेताओं का चयन किया जाएगा।



केंद्रीय टीम ने जनपद पंचायत सूरजपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत कुबेरपुर, सिलफिली एवं देवीपुर, विकासखंड भैयाथान के ग्राम पंचायत मासिस तथा प्रतापपुर विकासखंड के ग्राम पंचायत चंदौरा तथा प्रेमनगर विकासखंड के केदारपुर में जल संरचनाओं का मैदानी निरीक्षण किया। केदारपुर टीम ने स्व सहायता समूह की महिलाओ से जल संरचनाओं के माध्यम से किए जा रहे खेती व आजीविका गतिविधियों की जानकारी ली। इस दौरान वाटर हार्वेस्टिंग कूप, कंटूर ट्रेंच, गेबियन चेक डैम, मिट्टी बांध सहित विभिन्न जल संरक्षण संरचनाओं का अवलोकन कर उनकी उपयोगिता एवं प्रभावशीलता का आकलन किया। ग्राम पंचायत देवीपुर में टीम ने अमृत सरोवर का निरीक्षण किया तथा मानचित्र के माध्यम से क्षेत्र में विकसित जल संरक्षण संरचनाओं एवं जल प्रबंधन कार्यों की विस्तृत जानकारी प्राप्त की। निरीक्षण के दौरान केंद्रीय टीम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 'कैच द रेन' अर्थात 'जल जहां गिरे, वहीं सहेजें' के मूल मंत्र को सूरजपुर जिले में धरातल पर आत्मसात किया जा रहा है। ग्राम पंचायत चंदौरा में केंद्रीय अधिकारियों ने ग्रामीणों से सीधे संवाद कर जल संरक्षण कार्यों से आए बदलावों की जानकारी ली। केंद्रीय टीम ने खेतों में लहलहाती खरीं सहित अन्य फसलों को देखकर प्रसन्नता व्यक्त की। केंद्रीय निरीक्षण दल ने जिले के प्रमुख पर्यटन स्थल केनापारा का भी भ्रमण किया। इस दौरान टीम ने बोटिंग के माध्यम से जलाशय का अवलोकन कर जल संरक्षण के साथ विकसित पर्यटन एवं आजीविका गतिविधियों की जानकारी ली। टीम ने स्व-सहायता समूह की महिलाओं द्वारा संचालित फ्लोटिंग रेस्टोरेंट, बोटिंग एवं मत्स्य पालन सहित अन्य आजीविका गतिविधियों का निरीक्षण किया। केंद्रीय अधिकारियों ने जल संसाधनों का उपयोग पर्यटन विकास, महिला सशक्तिकरण एवं स्थानीय रोजगार सृजन के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में संचालित जल संचय जनभागीदारी अभियान के अंतर्गत कलेक्टर श्रीमती रेना जमील के मार्गदर्शन में जिले में 'मोर गांव, मोर पानी' की भावना के अनुरूप जल संरक्षण एवं संवर्धन के कार्यों को प्राथमिकता दी जा रही है। जिले ने जल संचय जनभागीदारी अभियान 2.0 में छत्तीसगढ़ में प्रथम एवं राष्ट्रीय स्तर पर चौथा स्थान हासिल किया है। अब 7वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2026 के लिए जिले का शॉर्टलिस्ट होना जल संरक्षण के क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

प्रतापपुर खरीदी केंद्र में एसडीएम के निरीक्षण में मिला सौ क्विं. नया व पुराना मिक्स धान

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

सूरजपुर। कलेक्टर श्रीमती रेना जमील के मार्गदर्शन में जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी व्यवस्था को पारदर्शी एवं सुव्यवस्थित बनाए रखने के उद्देश्य से प्रशासन द्वारा लगातार निगरानी एवं जांच की जा रही है। इसी क्रम में रमेश मोर एसडीएम प्रतापपुर द्वारा आदिम जाति सेवा सहकारी समिति प्रतापपुर का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान ग्राम पंचायत सिलौटा के किसान लखनराम द्वारा विक्रय हेतु लाए गए 250 बोरी लगभग 100 क्विंटल धान में नया एवं पुराना धान पाया गया। इस पर प्रशासनिक टीम द्वारा कार्रवाई करते हुए संपूर्ण 250 बोरी धान जब्त कर समिति प्रबंधक प्रतापपुर की सुपुर्दगी में दिया गया। जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाए रखने तथा संभावित अनियमितताओं पर प्रभावी नियंत्रण के लिए प्रशासन द्वारा उपार्जन केंद्रों की सतत निगरानी की जा रही है। निरीक्षण के दौरान धान की आवक, गुणवत्ता एवं खरीदी से संबंधित व्यवस्थाओं की जांच की जा रही है, ताकि शासन के निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप पात्र किसानों से धान खरीदी सुनिश्चित की जा सके।

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी (सा.) मनेन्द्रगढ़ वनमण्डल, मनेन्द्रगढ़ (छ.ग.)

नीलाम विज्ञापन

सामान्य सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है, कि मनेन्द्रगढ वनमण्डल के अधीनस्थ काष्ठागार जनकपुर में उपलब्ध पुराना ईमारती काष्ठ का दर्शित तिथि व समय में ई-ऑक्सन द्वारा निवर्तन किया जाना है, इच्छुक व्यापारी ई-ऑक्सन में अवश्य भाग लेवे। ई-ऑक्सन की शर्तें एवं अन्य जानकारी कार्यालयीन दिवस व समय पर वनमण्डल कार्यालय अथवा काष्ठागार जनकपुर से प्राप्त कर सकते है।

डिपो का नाम – काष्ठागार जनकपुर
नीलाम दिनांक – 27-11-2026
नीलाम समय – दोपहर 02:00 बजे से प्रारम्भ

क्र	प्रजाति	नये अविक्रित काष्ठ		पुराने अविक्रित काष्ठ			
		लट्ठा	बल्ली	लट्ठा		बल्ली	
		घ.मी.	नग	नग	घ0मी0	नग	घ.मी.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सागौन	0.000	0	178	10.901	896	10.238
2	साल	0.000	0	12045	1273.164	2576	80.608
3	साजा	0.000	0	22	2.033	4	0.122
4	धावड़ा	0.000	0	2	0.096	0	0.000
5	हल्दू,मुण्डी,बांसा	0.000	0	2	0.087	0	0.000
6	नीलगिरी	0.000	0	0	0.000	560	2.993
	योगः–	0	0	12249	1286.281	4036	93.961
7	मिश्रित जलाऊ	-		-			
	योग :–	-		-			

टीप :– 1. केता को ई-ऑक्सन के पूर्व MSTC E-commerce पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है।
2. केताओं को ई-ऑक्सन के पूर्व कय लॉटों के अपसेट प्राईज मूल्य के 10 प्रतिशत की राशि अपने वॉलेट में रखना अनिवार्य है, सफल बोलीदार को एक सप्ताह के भीतर 15 प्रतिशत E.M.D. की राशि जमा करना अनिवार्य है।
3. लॉट की थप्पी एवं फोटो MSTC E-commerce पोर्टल में अपने आई.डी से लॉगईन करके देख सकते है।

वनमण्डलाधिकारी
मनेन्द्रगढ़ वनमण्डल, मनेन्द्रगढ़

जी–262704569 / 2

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे

रुचि की अभिव्यक्ति

रेलवे स्वास्थ्य केन्द्र, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, मनेन्द्रगढ़ में पैथोलॉजीकल टेस्ट जॉब सुविधा का तीन वर्षों के लिए आउटसोर्सिंग का विज्ञापन।

मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, बिलासपुर के द्वारा रेलवे स्वास्थ्य केन्द्र, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे मनेन्द्रगढ़ से 05 कि.मी. के भीतर पैथोलॉजीकल टेस्ट जॉब सेंटर से रेलवे हितग्राहियों के लिए वर्तमान सी.जी.एच.एस दर (एन.ए.बी.एल./नान-एन.ए.बी.एल.) में जॉब सेवाएं देने के लिए रुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित की जाती है।

रुचि की अभिव्यक्ति प्राप्त होने के बाद रेलवे द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार प्राप्त ऑफरों को सारणित किया जाएगा। ऐसे केन्द्र जो सभी मानकों के मापदण्डों को पूरा करेगें उन्हें ही सूची में शामिल किया जाएगा। रेलवे स्वास्थ्य केन्द्र, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे मनेन्द्रगढ़ से 05 कि.मी. के भीतर इच्छुक पैथोलॉजीकल टेस्ट जॉब सेंटर से निवेदन है कि वे अपने रुचि की अभिव्यक्ति को (व्यक्तिगत अथवा रजिस्टर्ड डाक द्वारा) निर्धारित प्रोफार्मा में इस विज्ञापन के प्रकाशित होने के 21 दिनों के भीतर, कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, बिलासपुर में किसी भी कार्यालयीन दिवस में **11:00 बजे से 17:00 बजे तक** जमा कर सकते हैं। सभी केन्द्र जो सूचीबद्ध किए जायेंगें, निर्धारित दरें आगामी 03 वर्षों के लिए प्रभावी होंगें जो अपरिवर्तित रहेंगें एवं परिवर्तन केवल सी.जी.एच.एस दर के बदलने पर ही संभव हो सकेगा।

निर्धारित मापदण्ड, आवेदन के प्रोफार्मा और जाँचों की सूची, कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, बिलासपुर में उपलब्ध है तथा इसे द.पू.म. रेलवे के वेबसाईट **www.secr.indianrailways.gov.in** से दिनांक **20.11.2026 to 11.12.2026** तक डाउनलोड भी किया जा सकता है।

मुख्य चिकित्सा अधीक्षक (प्रभारी)
द.पू.म.रेलवे/बिलासपुर

सीपीआर/10/500

कूटरचना करके नए खसरा नम्बर का सृजन, निजी व्यक्ति के नाम पर किया

आजाद इराकी व पटवारी सहित 4 के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश

❐ छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

अंबिकापुर। कलेक्टर सरगुजा ने तहसील दरिमा के ग्राम दरिमा में स्थित भूमि खसरा क्रमांक 1322 रकबा 1.117 हे. एवं खसरा क्रमांक 1322/2 रकबा 2.202 हे. भूमि से संबंधित मामले में तहसीलदार दरिमा के जांच प्रतिवेदन के आधार पर आजाद इराकी सहित 4 व्यक्तियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने के निर्देश तहसीलदार दरिमा को दिए हैं। साथ ही रजिस्ट्री को निरस्त कराने के लिए सिविल वाद दायर करने हेतु पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने कहा गया है।

जानकारी के अनुसार राजस्व अभिलेखों में हेराफेरी कर भूमि खसरा क्रमांक 1322 रकबा 2.76 एकड़ (1.117 हे.) भूमि को खसरा नंबर 1322/2 के रूप में नई प्रविष्टि दर्ज किए जाने का मामला कलेक्टर के संज्ञान में आया था। मामले में जांच के दौरान सामने आया कि सिंहदेव योजनांतर्गत वर्ष 1968-69 में शासकीय पट्टेदार चंदर पिता बजरंग पनिका को ग्राम दरिमा स्थित खसरा नंबर 1322 की कुल 2.76 एकड़ भूमि का पट्टा प्रदान किया गया था। जांच प्रतिवेदन के अनुसार वर्ष 2016-17 के खसरा पांचशाला अभिलेख में खसरा नंबर 1322 का रकबा 1.117 हेक्टेयर दर्ज था। इसके बाद कंप्यूटरीकृत खसरा पांचशाला में खसरा नंबर 1322 को बटांकित कर हस्तलिखित अंकित कर खसरा नंबर 1322/1 रकबा 1.117 हेक्टेयर तथा खसरा नंबर 1322/2 रकबा 2.202 हेक्टेयर दर्ज किया गया। खसरा नंबर 1322/2 को बलिराम पिता रामप्रसाद के नाम पर दर्ज किया गया और कैफियत कॉलम नंबर 12 में हस्तलिखित खसरा लुप्त होने का उल्लेख किया गया। उक्त खसरा में प्रविष्टि किये जाने के संबंध में कोई भी सक्षम आदेश व अनुमोदन की प्रविष्टि खसरा में नहीं है, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि किस सक्षम अधिकारी के आदेश से उक्त प्रविष्टि की गई है। ऐसे में स्पष्ट हुआ कि खसरा नंबर 1322/2 को निजी व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से कूटरचना कर प्रविष्टि की गई है, क्योंकि खसरा नंबर 1322/2 का कोई विधिक अस्तित्व ही नहीं है।



जांच में यह भी सामने आया कि मूल खसरा नंबर 1322 के रकबे में कमी किए बिना अलग से खसरा नंबर 1322/2 सृजित कर 2.202 हेक्टेयर भूमि बलीराम के नाम दर्ज की गई। इसके बाद 18 जुलाई 2023 को तत्कालीन पटवारी द्वारा ऑनलाइन राजस्व दस्तावेजों में भूमि के नामांतरण से संबंधित प्रविष्टि की गई। तत्पश्चात 11 सितंबर 2023 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से उक्त भूमि को आजाद इराकी पिता रियाजुद्दीन इराकी तथा रामाशंकर सिंह पिता रामजस सिंह को विक्रय किया गया। कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में जांच प्रतिवेदन के आधार पर स्पष्ट किया गया है कम्प्यूटरीकृत खसरा पांचशाला में खसरा नम्बर 1322 को बटांकित कर हस्तलिखित अंकित कर खसरा नम्बर 1322/1 रकबा 1.117 हे. करते हुए खसरा नम्बर 1322/2 रकबा 2.202 हे. दर्ज कर बलीराम पिता रामप्रसाद के नाम पर कूटरचना कर दर्ज कर दिया गया है तथा कैफियत कॉलम नंबर 12 में कारण हस्तलिखित में 'लुप्त खसरा होने से अंकित किए जाने का उल्लेख किया गया है। उक्त प्रविष्टि के संबंध में सक्षम आदेश एवं अनुमोदन उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार राजस्व अभिलेखों में कूटरचना कर भूमि को निजी व्यक्ति के नाम दर्ज करने तथा उसके आधार पर विक्रय किए जाने का मामला सामने आया।

इनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने के निर्देश

कलेक्टर ने विक्रेता बलीराम पिता रामप्रसाद निवासी ग्राम खजुरी तहसील दरिमा जिला सरगुजा तथा क्रेता आजाद इराकी पिता रियाजुद्दीन इराकी निवासी जयनगर तहसील लटोरी जिला सूरजपुर एवं रामाशंकर सिंह पिता रामजस सिंह निवासी विश्रामपुर जिला सूरजपुर सहित ग्राम दरिमा के तत्कालीन पटवारी अनिरुद्ध कुमार पैकरा के विरुद्ध संबंधित थाने में सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कराकर पालन प्रतिवेदन तत्काल प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही रजिस्ट्री को निरस्त कराने के लिए सिविल वाद दायर करने तथा अवैध प्रविष्टि को विलोपित करने हेतु आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को निर्देशित किया गया है।



मुख्यमंत्री की पहल पर जशपुर को दूसरी रेल लाइन की सौगात, केंद्र ने दी हरी झंडी

❐ छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

जशपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जशपुरवासियों को दूसरी रेल लाइन की सौगात दी है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने 27 अक्टूबर 2026 को ओडिशा के सरडेगा से छत्तीसगढ़ के पत्थलगांव होते हुए अंबिकापुर तक 218 किलोमीटर रेल लाइन परियोजना को हरी झंडी देते हुए राजपत्र में प्रकाशित कर दिया है। इससे पहले केंद्र सरकार झारखंड के लोहरदगा से धर्मजयगढ़ तक की रेल लाइन को विशेष रेल परियोजना में शामिल करते हुए केंद्रीय राजपत्र में प्रकाशित कर चुकी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार द्वारा प्रभार संभालने के महज तीन साल के भीतर ही जिले में दूसरी रेल लाइन की स्वीकृति मिलने से जशपुरवासियों में उत्साह और उमंग देखने को मिल रहा है।

इस रेल लाइन के बन जाने से ओडिशा, छत्तीसगढ़ और झारखंड रेल लाइन से जुड़ जाएंगे। इस प्रस्तावित रेल लाइन के लिए सर्वेक्षण का काम पहले ही पूरा कर लिया गया है। सर्वे रिपोर्ट के अनुसार सरडेगा से पत्थलगांव तक 128 किलोमीटर और पत्थलगांव से अंबिकापुर की दूरी 90 किलोमीटर है। उल्लेखनीय है कि विशेष रेल लाइन को केंद्र सरकार ने सामान्य परियोजनाओं से अलग, प्राथमिकता वाली परियोजना के रूप में चिन्हांकित किया है। ऐसी परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण, वन स्वीकृति, पर्यावरणीय अनुमति और अन्य विभागीय प्रक्रियाओं में तेजी लाई जाती है। इसके लिए अलग से फंड और समय-सीमा तय होती है, ताकि परियोजना को लंबित होने से बचाया जा सके। डबल इंजन सरकार के डबल उपहार से जशपुर में उल्लासतीन साल के कार्यकाल में जशपुर जिले में दूसरी रेल लाइन को केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृति दिए जाने से जशपुरवासियों का उत्साह देखते ही बनता है। इस दोहरे उपहार से आदिवासी बहुल जशपुर जिले के विकास को नई ऊंचाई मिलेगी। रेल लाइन के माध्यम से जशपुर, रायगढ़, बिलासपुर, रायपुर, रांची, कोलकाता जैसे बड़े शहरों से संपर्क आसान हो जाएगा। इससे यहां के व्यवसाय का विस्तार हो सकेगा। इसी उम्मीद से जिलेवासी 70 के दशक से लोहरदगा-कोरबा रेल लाइन की मांग कर रहे थे, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली प्रदेश सरकार ने पूरा कर दिखाया है।

जशपुर में अपराधियों पर शिकंजा, डीआईजी ने ली क्राइम समीक्षा बैठक, नशा-पशु तस्करी पर बड़ा एक्शन

❐ छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

जशपुर। पुलिस अधीक्षक कार्यालय जशपुर के सभागार में 18 नवम्बर 2026 को डीआईजी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेद सिंह ने जिले के समस्त राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना-चौकी प्रभारियों की अपराध समीक्षा बैठक ली। बैठक में कानून-व्यवस्था, अपराध नियंत्रण, लंबित प्रकरणों के निराकरण, पुलिसिंग की गुणवत्ता एवं विभिन्न अभियानों की विस्तृत समीक्षा की गई।

पुलिस कप्तान ने सभी थाना-चौकी प्रभारियों को लंबित अपराध, मर्ग, शिकायत एवं अन्य प्रकरणों का गंभीरता से अवलोकन कर शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लंबित मामलों में अनावश्यक विलंब न हो और प्रत्येक प्रकरण में समयबद्ध कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

अवैध मादक पदार्थों की तस्करी एवं पशु तस्करी की रोकथाम को लेकर विशेष जोर दिया गया। मुखबिरी व्यवस्था को मजबूत बनाने, स्थानीय स्तर पर सूचना तंत्र सक्रिय रखने और संदिग्ध गतिविधि की जानकारी मिलने पर तत्काल प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए। सभी थाना-चौकी के बीच आपसी समन्वय व सूचनाओं के आदान-प्रदान तथा आवश्यकता पड़ने पर संयुक्त कार्यवाही करने पर भी जोर दिया गया।

डायल 112 की कार्यप्रणाली की समीक्षा करते हुए आपातकालीन सूचनाओं पर त्वरित प्रतिक्रिया, मौके पर शीघ्र पहुंचने और पीड़ितों को तत्काल सहायता देने के निर्देश दिए गए। अपराधों की विवेचना में आधुनिक तकनीकी संसाधनों का अधिक से अधिक उपयोग करने, तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर गुणवत्तापूर्ण निराकरण करने को कहा गया।

ऑपरेशन ईगल के तहत फरार स्थाई वारंटियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष निर्देश दिए गए। सभी प्रभारियों को अपने क्षेत्र के फरार स्थाई वारंटियों की जानकारी अद्यतन रखने, पतासाजी के लिए प्रभावी प्रयास करने और अधिक से अधिक वारंटियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत करने को कहा गया।

प्राकृतिक आपदा, पानी में डूबने, सर्पदंश व अन्य आकस्मिक मृत्यु के मामलों में पीड़ित परिवारों को राहत राशि दिलाने के प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करने, प्रतिवेदन यथाशीघ्र भेजने के निर्देश दिए गए। सीएम पोर्टल व अन्य ऑनलाइन पोर्टलों पर प्राप्त शिकायतों का निर्धारित समय-सीमा में त्वरित व संतुष्टिपूर्ण निराकरण करने को कहा गया।

थाने आने वाले पीड़ितों से सरल, सहज व संवेदनशील व्यवहार रखने, समस्याएं गंभीरता से सुनने और प्रकृति के अनुसार प्राथमिकता से वैधानिक कार्यवाही व अपराध पंजीबद्ध करने के निर्देश दिए गए। सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए यातायात जागरूकता अभियान को प्रभावी ढंग से चलाने, स्कूल-कॉलेजों व ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यक्रम आयोजित करने, हेलमेट, सीट बेल्ट व गति सीमा के पालन के प्रति जागरूक करने को कहा गया। प्रशिक्षु उप निरीक्षकों के कार्यों की भी समीक्षा कर पुलिसिंग की बारीकियां गंभीरता से सीखने के निर्देश दिए गए।

बैठक के बाद गंभीर मामलों में उत्कृष्ट विवेचना करने वाले विवेचकों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। वहीं गुड सेमेरिटन के तहत 06 नवम्बर की रात्रि करीब 09 बजे घाघरा-छतीरी जंगल में स्कॉर्पियो व पिकअप दुर्घटना में घायलों को बाहर निकालकर अस्पताल व पुलिस को सूचित करने वाले दो पुलिस मितानों विजय कुमार सिदार (40 वर्ष) व ओस्वीन जेराल तिर्की (32 वर्ष), दोनों निवासी ग्राम घाघरा, को हेलमेट एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। बैठक में जिले के समस्त राजपत्रित अधिकारी, थाना-चौकी प्रभारी एवं एसपी कार्यालय का स्टाफ उपस्थित रहा।



वित्त मंत्री ने भगवान बिरसा मुंडा चौक पर प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया नमन

❐ छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

जशपुरनगर। वित्त मंत्री एवं जशपुर जिले के प्रभारी मंत्री ओपी चौधरी ने आज जशपुर में भगवान बिरसा मुंडा चौक पहुंचकर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन किया।इस अवसर पर चौधरी ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा भारत के महान आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी, जननायक और समाज सुधारक थे। उन्होंने आदिवासी समाज को एकजुट कर अंग्रेजी शासन और शोषणकारी व्यवस्था के विरुद्ध संघर्ष किया। उन्होंने आदिवासी समाज को जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए जागरूक किया तथा समाज में स्वाभिमान, एकता और अधिकारों के प्रति चेतना जगाई।उन्होंने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा का त्याग, संघर्ष और बलिदान सदैव देशवासियों के लिए प्रेरणास्रोत रहेगा।इस अवसर पर जशपुर विधायक रायमुनि भगत, नगर पालिका अध्यक्ष अरविंद भगत, जनपद पंचायत अध्यक्ष गंगाराम भगत, पूर्व राज्यसभा सांसद रणविजय सिंह जुदेव, कृष्णा राय, भरत सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेद सिंह, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अभिषेक कुमार सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं अधिकारीगण बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।



❐ छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

जशपुर। बुधवार को कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन ने 37 दिन से चल रही पटवारी संघ की हड़ताल का समर्थन किया। फेडरेशन के पदाधिकारी और कर्मचारी पटवारियों के साथ रैली में शामिल हुए। रैली के बाद कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में पटवारी संघ की चारों मांगें पूरी करने, पटवारियों पर की गई कार्रवाई रद्द करने और 3 प्रतिशत लंबित महंगाई भत्ता देने की मांग की गई। फेडरेशन ने मांगें पूरी नहीं होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी।

रैली निकालकर सरकार के खिलाफ लगाए नारे

फेडरेशन के पदाधिकारी और कर्मचारी पटवारी संघ के साथ रैली में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने सरकार के खिलाफ नारे लगाए। रैली के बाद कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर पटवारियों की मांगें पूरी करने की अपील की गई।

नोटिस और निलंबन की कार्रवाई का विरोध

फेडरेशन के संतोष टांडे ने बताया कि पटवारी संघ चार मांगों को लेकर 37 दिन से आंदोलन कर रहा है। सरकार ने मांगें पूरी करने की पहल करने के बजाय पटवारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए। साथ ही निलंबन और सर्विस बेक जैसी कार्रवाई की गई।टांडे ने कहा कि फेडरेशन सरकार की इस कार्रवाई का विरोध करता है और पटवारी संघ की मांगों का समर्थन करता है। दोनों संगठनों ने मिलकर रैली निकाली और ज्ञापन सौंपा। मांगें पूरी नहीं होने पर फेडरेशन आंदोलन तेज करेगा।

बातचीत के बाद भी नहीं निकला समाधान

पटवारी संघ के जिलाध्यक्ष विनय श्रीवास्तव ने बताया कि 37 दिन से चल रही हड़ताल खत्म कराने की कोशिश अब तक सफल नहीं हुई है। सरकार और संघ के पदाधिकारियों के बीच बातचीत हुई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। उन्होंने कहा कि कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन का समर्थन मिलने से सरकार पर दबाव बढ़ेगा। इससे हड़ताल खत्म करने और गतिरोध दूर करने का रास्ता निकल सकता है।

पटवारियों पर कार्रवाई के विरोध में फेडरेशन सड़क पर, मांगें नहीं मानी तो होगा बड़ा आंदोलन

पीएम मोदी ने जनजातीय गौरव दिवस से आदिवासी महानायकों को दिलाई नई पहचान : ओपी चौधरी

❐ छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

जशपुरनगर। सरना एथलेटिक रिजॉर्ट बालछापार में जनजातीय गौरव दिवस का गरिमामय आयोजन हुआ। मुख्य अतिथि वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने भगवान बिरसा मुंडा सहित जनजातीय महानायकों को नमन किया और वीर शहीदों के परिजनों व समाज प्रमुखों को शॉल-श्रीफल भेंटकर सम्मानित किया। वित्त मंत्री ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाने की शुरुआत कर आदिवासी इतिहास व महानायकों को नई पहचान दिलाई। अब इसे सभी वर्ग मनाते हैं। आदिवासी बेटी द्रौपदी मुर्मु राष्ट्रपति बनीं और जशपुर की माटी के बेटे विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री बने, यह गौरव की बात है।



चौधरी ने कहा कि भारतमाता, रेल लाइन, कुनकुरी में मेडिकल कॉलेज, जशपुर में नालंदा परिसर और वनवासी कल्याण आश्रम में एनटीपीसी से आधुनिक अस्पताल के निर्माण से जशपुर की तस्वीर बदल रही है। उन्होंने कहा कि प्रयास विद्यालयों से आईआईटी, मेडिकल, सीए, लॉ की निशुल्क तैयारी हो रही है। जनजातीय विभाग से दिल्ली में सिविल सेवा की तैयारी के लिए 3.5 से 4 लाख रुपये की सहायता मिल रही है। उन्होंने कहा, मैं छोटे गांव से 22 साल में आईएएस बना, तो जशपुर के बच्चे कलेक्टर, एसपी, डॉक्टर, इंजीनियर क्यों नहीं बन सकते। चौधरी ने संस्कृति को नई पीढ़ी तक पहुंचाने पर जोर दिया और प्रत्येक सांस्कृतिक दल को 10-10 हजार रुपये स्वेच्छानुदान देने की घोषणा की।

विधायक ने कुरुख बोली में गीत के माध्यम से किया जनजातीय वीरों का स्मरण

विधायक ने कुरुख गीत में बिरसा मुंडा, सिदो-कान्हू, तिलका मांझी, वीर चुंडु भगत, वीर नारायण सिंह को याद किया और धरमजयगढ़-पत्थलगांव-लोहरदगा रेल लाइन व रायपुर-धनबाद कॉरिडोर का उल्लेख किया।

मंत्री ने पहाड़ी कोरवा लोगों से मुलाकात कर सम्मानित किया। अंडर-17 व अंडर-19 राष्ट्रीय क्रिकेट टीम में चयनित जशपुर की बेटियों का उत्साहवर्धन किया। मुद्रा लोन में शकुंतला सिंह को 1 लाख, सुमित्रा बेसरा व बंधनी बाई को 2-2 लाख के प्रतीकात्मक चेक दिए।

कार्यक्रम में पद्मश्री जागेश्वर यादव, पूर्व सांसद रणविजय सिंह जूदेव, जिला पंचायत अध्यक्ष सालिक साय, नगर पालिका अध्यक्ष अरविंद भगत, एसएसपी डॉ. लाल उमेद सिंह, सीईओ अभिषेक कुमार सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे।

जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम पात्र हितग्राही तक पहुंचाना सुनिश्चित करें - वित्त मंत्री

❐ छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

जशपुरनगर। प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी आज जशपुर जिले में आयोजित जनजातीय गौरव दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने सर्वप्रथम बिरसा मुंडा चौक पहुंचकर महान स्वतंत्रता सेनानी एवं जनजातीय समाज के गौरव भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए। इसके पश्चात् मंत्री चौधरी सरना एथलिक रिसॉर्ट में आयोजित जनजातीय गौरव दिवस समारोह में शामिल हुए।

समारोह स्थल पर पहुंचकर उन्होंने विभिन्न विभागों द्वारा शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं पर आधारित लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने महिला एवं बाल विकास विभाग के स्टॉल पर पहुंचकर स्थानीय व्यंजनों का स्वाद लिया। उन्होंने वहां तैयार उड़द के बड़े एवं चावल से बने पारंपरिक फरा का सेवन किया तथा प्रति प्लेट निर्धारित राशि का भुगतान भी किया। स्टॉल निरीक्षण के दौरान मंत्री चौधरी ने संबंधित अधिकारियों से विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी ली। उन्होंने विशेष रूप से यह जानकारी प्राप्त की कि शासन की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम पात्र हितग्राही तक पहुंच रहा है अथवा



नहीं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करते हुए पात्र हितग्राहियों को समयबद्ध तरीके से लाभान्वित किया जाए। साथ ही आम नागरिकों को योजनाओं की पात्रता एवं लाभ की प्रक्रिया के संबंध में जागरूक करने पर भी जोर दिया।

इस अवसर पर मंत्री चौधरी ने महान स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक एवं जनजातीय अस्मिता के महानायक धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन करते हुए समस्त प्रदेशवासियों को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा का संपूर्ण जीवन मातृभूमि की स्वतंत्रता, जनजातीय समाज के अधिकारों, स्वाभिमान एवं सामाजिक न्याय के लिए समर्पित रहा। उनका संघर्ष, त्याग और बलिदान सदैव देशवासियों को प्रेरित करता रहेगा। विभागीय स्टॉलों के निरीक्षण के पश्चात् मंत्री चौधरी मुख्य मंच की ओर अग्रसर हुए, जहां जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर आयोजित मुख्य समारोह में शामिल हुए।

कार्यक्रम में पद्मश्री सम्मानित जागेश्वर यादव, जशपुर विधायक रायमुनि भगत, पूर्व राज्यसभा सांसद रणविजय सिंह जूदेव, छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम के नवनियुक्त अध्यक्ष सुरेन्द्र कुमार बेसरा, जिला पंचायत अध्यक्ष सालिक साय, राम गर्ग, नगर पालिका अध्यक्ष अरविंद भगत, जनपद पंचायत अध्यक्ष गंगाराम भगत, जिला पंचायत सदस्य गेंद बिहारी सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेद सिंह, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अभिषेक कुमार, भरत सिंह, कृष्ण कुमार राय, एसडीएम सहित जनप्रतिनिधि, विभिन्न जनजातीय समाजों के प्रमुख एवं प्रतिनिधि, अधिकारी-कर्मचारी, गणमान्य नागरिक तथा बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे।

कॉलेज में खाद्य मिलावट पर जागरूकता कार्यक्रम, 185 प्रतिभागियों ने सीखे मिलावट पहचानने के आसान तरीके

❐ छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

जशपुरनगर। राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान, कुंडली, हरियाणा की 19 सदस्यीय टीम नौ दिवसीय ग्राम गोद कार्यक्रम पर जशपुर में है। टीम का नेतृत्व प्रो. प्रसन्न कुमार जी.वी. और डॉ. अभिमन्यु गौर कर रहे हैं। कार्यक्रम कलेक्टर रोहित व्यास के सहयोग से हो रहा है। पहले दिन शासकीय आरबीआरएनईएस पीजी कॉलेज, जशपुर में "खाद्य मिलावट : जागरूकता एवं जांच के तरीके" पर कार्यक्रम हुआ, जिसमें 185 प्रतिभागी शामिल हुए। टीम ने प्राचार्य डॉ. अमरेन्द्र व प्राध्यापकों से भी विचार-विमर्श किया। कार्यक्रम में भाषण के बजाय साधारण रासायनिक परीक्षणों व प्रत्यक्ष प्रदर्शन से मिलावट पहचानना सिखाया गया। आटा-दाल-बेसन, दूध में स्टार्च-डिटर्जेंट-यूरिया-न्यूट्रलाइजर, पनीर-घी-शहद-तेल, हल्दी-मिर्च में कृत्रिम रंग व मेटानिल येलो, सरसों तेल में आर्जीमोन ऑयल और सब्जियों में मिलावट की पहचान बताई गई। घर पर किए जा सकने वाले प्रारंभिक परीक्षण व सैंपल तैयार करने की विधि भी समझाई गई। यह भी स्पष्ट किया गया कि अंतिम पुष्टि के लिए मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला जांच जरूरी है।

विशेषज्ञों ने कहा कि मिलावटी भोजन के लंबे सेवन से पेट, लीवर, किडनी और बच्चों के विकास पर बुरा असर पड़ता है। सुरक्षित भोजन का चुनाव ही सबसे बड़ी सुरक्षा है।कार्यक्रम में डॉ. सरिता निकुंज, डॉ. जे. तिर्की, डी. आर. राठिया, सुश्री एलिन एक्का सहित प्राध्यापक व विद्यार्थी उपस्थित रहे। आगामी दिनों में टीम मिलेट्स व मिलेट उत्पाद, महुआ के गुण, खाद्य प्रसंस्करण उद्यमिता, प्रशिक्षण-लाइसेंसिंग व खाद्य सुरक्षा पर कार्यक्रम करेगी। टीम कुनकुरी में किसानों को बेकरी उत्पाद व खाद्य प्रसंस्करण का प्रैक्टिकल प्रशिक्षण भी देगी। उद्देश्य स्थानीय संसाधनों का मूल्य संवर्धन, ग्रामीण कौशल विकास और स्वरोजगार को बढ़ावा देना है।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक मनीष पाठक द्वारा स्पीड प्रिंटर्स व ऑफसेट पुराना पोस्ट ऑफिस रोड दरीपारा अंबिकापुर छ. ग. पिन नं. 497001 से मुद्रित व वार्ड क्र. 10 कुनकुरी जशपुर से प्रकाशित। संपादक - लक्ष्मण सिंह